सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

"तारीफ चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं। जबकि, अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। ...!!"

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–164 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 03 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

मानसून सत्र में टकराव तय

130वां संविधान संशोधन बिल – नैतिक राजनीति की कसौटी या सियासी हथियार?

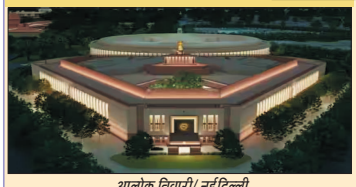

आलोक तिवारी/ नई दिल्ली

30 दिन जेल में रहने पर PM-CM की जाएगी कुर्सी

मोदी सरकार मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। यह बिल भारतीय राजनीति की दशा-दिशा तय कर सकता है। इसके तहत 5 साल या अधिक सजा वाले अपराध में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट 17 जुलाई को सौंपी जानी है और 20 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में बिल पेश होने के आसार हैं।

बिल के पीछे का सियासी संदर्भ

यह प्रस्ताव सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल प्रकरण से जुड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर बने रहने और जेल से सरकार चलाने की कोशिश ने "जेल से शासन" की बहस छेड़ दी थी। सरकार का तर्क है कि गंभीर आरोपों में घिरे व्यक्ति का पद पर बने रहना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। बिल इसी शून्य को भरने की कोशिश है।

कानूनी कसौटी पर सवाल

बिल का सबसे बड़ा कानूनी पेच 'दोषी साबित होने तक निर्दोष' का सिद्धांत है। भारतीय न्यायशास्त्र में गिरफ्तारी दोषसिद्धि नहीं होती। विपक्ष का आरोप है कि बिना ट्रायल के पद से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। दूसरा सवाल 5 साल की सजा वाले अपराधों की परिभाषा का है। कई जन आंदोलनों से जुड़ी धाराओं में भी 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है।

संसद में नंबर का गणित

संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए।

- **राज्यसभा:** एनडीए जरूरी आंकड़े के करीब है। वाईएसआरसीपी, बीजेडी जैसे दलों का रुख अहम होगा।
- **लोकसभा:** यहां दो-तिहाई का आंकड़ा जुटाना सरकार के लिए चुनौती है। टीडीपी, जेडीयू जैसे सहयोगियों के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय दलों का समर्थन जरूरी होगा।

विपक्ष की चिंता : 'राजनीतिक हथियार' का डर

INDIA गठबंधन ने बिल को लोकतंत्र विरोधी बताया है। मुख्य आपत्ति यह है कि केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी मुख्यमंत्रियों को 30 दिन हिरासत में रखकर सरकारें गिराई जा सकती हैं। तमिलनाडु, झारखंड, दिल्ली के हालिया मामलों का हवाला दिया जा रहा है। विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर हमला मान रहा है।

सत्ता पक्ष का पक्ष : 'शुचिता बनाम अराजकता'

भाजपा का कहना है कि यह बिल राजनीति में शुचिता लाएगा। जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर गंभीर आरोपों में जेल जाता है तो नैतिक आधार पर उसे पद छोड़ना चाहिए। सरकार का तर्क है कि यह प्रावधान सभी दलों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह केंद्र हो या राज्य।

मानसून सत्र इस बिल के कारण हंगामेदार रहेगा। एक तरफ सरकार के लिए यह 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' का संदेश देने का मौका है। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह 'लोकतंत्र बचाओ' का मुद्दा बनेगा। अमित शाह की रणनीतिक कुशलता और विपक्षी एकजुटता, दोनों की असल परीक्षा संसद में होगी।

बिल पास होता है या नहीं, पर इतना तय है कि इसने 'सत्ता, नैतिकता और कानून' की बहस को नई धार दे दी है। आने वाले विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसकी गूंज सुनाई देगी।

नए कलेवर में चौपाटी पुष्पवाटिका, लक्ष्मण झुला भी हुआ शुरू

नेहरू उद्यान और आरके नगर उद्यान का भी हुआ संधारण, दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे पार्क

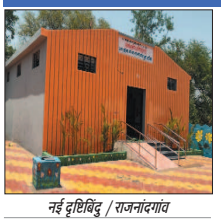

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

निगम सीमा क्षेत्र के जीणशीर्ण हो चुके उद्यानों को नई साज-सज्जा के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। शहर का प्रमुख चैपाटी पुष्पवाटिका, नेहरू उद्यान और आरके नगर उद्यान की मरम्मत कर वहां नए झूले और खेल उपकरण लगाए गए हैं। लंबे समय से बंद पड़ा लक्ष्मण झुला भी मरम्मत के बाद फिर से चालू कर दिया गया है। अब नागरिक दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक इन उद्यानों में स्वस्थ मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे।

लक्ष्मण झुला चालू होने से आवागमन आसान : निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि महापौर मधुसूदन यादव के निर्देश पर उद्यानों का संधारण किया जा रहा है। चैपाटी पुष्पवाटिका जर्जर हो गई थी। इसका प्रमुख हिस्सा लक्ष्मण झुला बंद था, जिसे

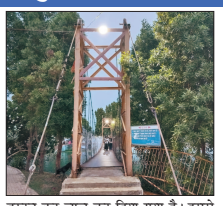

दुरुस्त कर चालू कर दिया गया है। इससे नागरिकों को चैपाटी से पुष्पवाटिका जाने में हो रही परेशानी खत्म होगी और वे पहले की तरह आसानी से आ-जा सकेंगे।

कबाड़ से जुगाड़: शेर बना सेल्फी पॉइंट

उद्यान के पाथवे की मरम्मत के साथ झूले और जिम उपकरण भी दुरुस्त किए गए हैं। कबाड़ से जुगाड़ के तहत अनुपयोगी सामग्री से शेर की आकृति बनाकर सेल्फी पॉइंट विकसित किया गया है। पुष्पवाटिका में नागरिकों की सुविधा के लिए सर्वसुविधायुक्त आकांक्षी शौचालय का भी निर्माण किया गया है।

बजट में प्रावधान, बाकी उद्यान भी सुधरेंगे : आयुक्त ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में महापौर द्वारा उद्यानों के संरक्षण-संवर्धन का प्रावधान रखा गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए विभागीय प्रक्रिया चल रही है। शीतला मंदिर समीप नेहरू उद्यान और

आरके नगर उद्यान का संधारण पूरा हो चुका है। शेष उद्यानों को भी प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा ताकि नागरिकों को सभी सुविधाएं मिल सकें।

रघुवर मार्ग पर अवैध प्लाटिंग का खेल नगर निगम को लग रहा लाखों का चूना

खरीददार फंसने को तैयार, कॉलोनाइजर ने काटी चांदी, निर्माण भी शुरू, नगर निगम मौन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

केशर नगर से लगे रघुवर मार्ग पर बेखौफ अवैध प्लाटिंग का कारोबार चल रहा है। नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनाइजर ने जमीन के टुकड़े कर लाखों में बेच दिए। इससे नगर निगम को लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ है और खरीददारों की जमा पूंजी फंसने के कगार पर है। हैरानी की बात यह है कि अवैध प्लॉटों पर मकान निर्माण भी शुरू हो चुका है, लेकिन निगम प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं।

निगम के अमले को भनक तक नहीं

शहर के बीचोंबीच हो रही इस अवैध प्लाटिंग पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम का पूरा अमला राजस्व वसूली के लिए हर वार्ड में जाता है, फिर भी अवैध कारोबार की भनक न लगना समझ से परे है। पूर्व में आउटर में ऐसे कारोबारियों पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन शहर के भीतर कार्रवाई न होने से कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद हैं।

खरीददारों पर लटकी तलवार, FIR का प्रावधान

कई लोगों ने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली है तो कईयों ने एडवांस दे दिया है। अब बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलेंगी, यह बड़ा सवाल है। अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर का प्रावधान है। आम लोगों को जंजाल में फंसाने को लेकर जिला और राज्य स्तर पर शिकायत की तैयारी है।

बिना एप्रूवल 15-20 फीट की मुरूम रोड

कॉलोनाइजर ने जमीन को दो हिस्सों में बांटकर बिना किसी एप्रूवल के बीच में 15 से 20 फीट पर मुरूम बिछाकर रोड बना दी। बिजली कैसे पहुंचेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। शिकायत में इन सभी बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा।

निगम बोला : टीम भेजकर जांच कराएंगे

प्रभारी नजूल भवन शाखा यूके रामटेके ने कहा कि जहां भी अवैध प्लाटिंग हो रही है, वहां सख्ती बरती जाएगी। रघुवर मार्ग पर टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और अन्य स्थानों पर भी संज्ञान लिया जाएगा।

शहर में मोतीपुर, नवागांव, बापूटोला, पेंड़ी समेत कई हिस्सों में अवैध प्लाटिंग चल रही है। निगम की माली हालत खराब होने के बावजूद राजस्व नुकसान पर सुस्ती सवाल खड़े कर रही है।

कांग्रेसी नेता का नाम आएगा सामने

एक तरफ कांग्रेस अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है, वहीं रघुवर मार्ग पर अवैध प्लॉट बेचने में कांग्रेसी नेता का ही नाम सामने आ रहा है। एक-दो दिन में होने वाली शिकायत के बाद नेता का नाम सार्वजनिक हो जाएगा। शिकायत के बाद खरीददारों की पूंजी अटकना तय है क्योंकि कॉलोनाइजर रकम लौटाने वाला नहीं है।

अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

आरोप है कि राजस्व प्रकरण देखने वाले और पटवारियों की जानकारी के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं। इसलिए नगर निगम के अधिकारी-कमर्चारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मामले की शिकायत जिला प्रशासन के साथ नगरीय प्रशासन विभाग से भी की जाएगी।

300 से अधिक फाइव स्टार होटलों में ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

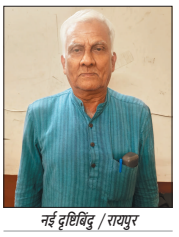

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

होटल हयात से लैपटॉप लेकर भागा था विन्सेंट जॉन, भुवनेश्वर से पकड़ा गया

क्राइम ब्रांच ने देशभर के फाइव स्टार होटलों को निशाना बनाने वाले अंतरराज्यीय शातिर ठग विन्सेंट जॉन को भुवनेश्वर, उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी होटल हयात, तेलीबांधा का बिल चुकाए बिना वहां का लैपटॉप लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से लैपटॉप जब्त कर लिया है।

चार्ल्स शोभराज से था प्रभावित

मूलतः तमिलनाडु निवासी आरोपी विन्सेंट जॉन शातिर ठग चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था। वह खुद को फॉरेन गाइड, इंग्लिश टीचर और योगा टीचर बताकर महंगे होटलों में रुकता और ठगी को अंजाम देता था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी देशभर में 300 से अधिक 5 स्टार होटलों में ठगी और चोरी कर चुका है।

15 साल जेल में काटे, 1990 से कर रहा ठगी

आरोपी के खिलाफ मेट्रोपोलिटन सिटीज सहित 10 से अधिक राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं। तिहाड़ जेल समेत देश के अलग-अलग राज्यों की जेलों में वह करीब 15 साल बंद रह चुका है। साल 1996 में वह पहली बार तिहाड़ जेल गया था। आरोपी ने 1990 से अपना जीवन जेलों और महंगे होटलों में ही गुजारा है।

Only Five Star Hotel को बनाता था निशाना

क्राइम ब्रांच के मुताबिक जॉन का दुश्मन सिर्फ फाइव स्टार होटल थे। वह होटलों में रुकने के बाद बिल दिए बिना लैपटॉप, मोबाइल जैसे कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। तेलीबांधा थाना इलाके के इस मामले का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

सीएम साय ने वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे के निधन पर जताया दु :ख

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे का हृदयाघात से निधन हो गया है। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे अपनी सादगी, निष्पक्ष पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे के निधन पर दुःख जताया है।

अंतरराज्यीय नशा तस्करी का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

16 लाख का गांजा, इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट जब्त, गैंग का सरगना 20 साल की सजा काट चुका

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कमिश्नरेट पुलिस की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने बैकवर्ड लिंक पर कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां, गांजा, इंजेक्शन और सिरिंज बरामद की गई है। जब्त सामान की कीमत करीब 16 लाख रुपये है।

पूर्व में पकड़े गए तस्कर से मिला सुराग

पूर्व में गिरफ्तार गांजा तस्कर अभिषेक कुमार से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 4 और आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी उड़ीसा, यूपी और छत्तीसगढ़

के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 किलोग्राम गांजा, 2,000 नाइट्रोटेन टैबलेट, 30 कोडिन सिरप, 290 पेंटाजोसीन इंजेक्शन, 300 सिरिंज और 3,100 रुपये नगद जब्त किए गए।

गैंग का सरगना 20 साल की सजा काट चुका

इस गैंग का सरगना किशोर साहू उड़ीसा का निवासी है। वह पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के मामले में 20 साल सश्रम कारावास से दंडित हो चुका है। वर्तमान में वह उच्च न्यायालय से जमानत पर था। प्रकरण में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों, सप्लायर और रिसीवर की पहचान कर END TO END कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ बैकवर्ड लिंक पर यह बड़ी कार्रवाई है और आगे भी ऐसे नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाएगा।

सेक्टर-2 टर्फ ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट, विजेता खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेक्टर-2 स्थित टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक रहा। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों से भेंट कर विजेता और प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए खेल भावना, अनुशासन और टीमवर्क के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

खिलाड़ियों से की आत्मीय भेंट : कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। अभिभावकों से चर्चा कर बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। विजेता टीमों के साथ-साथ सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

अतिथियों ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह, खेल भावना और अनुशासन पर दिया जोर

ये रहे मौजूद : इस अवसर पर सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, आयोजक दलबाग सिंह, सर्व समाज कल्याण समिति भिलाई के महासचिव मलकीत सिंह, उपाध्यक्ष जोगा राव, शाहनवाज कुरैशी, सुनील यादव, वाजिद अंसारी, पंकज सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

दुर्ग के सफल उद्यमी हैं मेघगंगा ग्रुप के चेयरमैन, सामाजिक कार्यों के लिए मनीष पारख को डॉक्टरेट की मानद उपाधि, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने किया सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मेघगंगा ग्रुप के चेयरमैन मनीष पारख को सामाजिक दायित्वों के क्षेत्र में लगातार किए गए कार्यों के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास बंडु आठवले द्वारा प्रदान किया गया।

'पिताजी की शिक्षा से मिला प्रेरणा' : मनीष पारख

मनीष पारख ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि सभी के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि व्यापार के साथ-साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ना उनके पिताजी की दी हुई शिक्षा और रास्ते का असर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, साइबर जागरूकता जैसे विषयों पर उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी उठाई है।

स्वास्थ्य से शिक्षा तक, कई क्षेत्रों में योगदान

लाइफकेयर डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन , 7 वर्षों से लगातार फ्री एम्बुलेंस सेवा का संचालन, रूटीन स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देने हेल्थ कार्ड की शुरुआत, स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। 'मोर शहर मोर जिम्मेदारी' के तहत गांधी चौक, शहीद चौक, वाय शेप ब्रिज चौक, कचहरी चौक का सौंदर्यीकरण, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग को वैरिकेड उपलब्ध कराए, महावीर स्कूल के अध्यक्ष के रूप में स्कूल का जीणोद्धार और झलिटी एजुकेशन के लिए प्रयास, 'साइबर प्रहरी' अभियान में दुर्ग पुलिस और रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग के साथ मिलकर साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता फैलाई। मनीष पारख दुर्ग जिले के सफल उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान व्यापार के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी है।

खास खबर

कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों से कलेक्टर ने किया संवाद, पढ़ाई और भविष्य पर की चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके दस बच्चों (प्रीति टंडन, करीना टंडन, स्पनिल बोस, दुष्यंत कुमार साहू, जयंत कुमार साहू, वैभव बंजारे, सुल्ताना खान, यमुना ठाकुर, जय ठाकुर, रविन्द्र कुमार टंडन) से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मुलाकात कर संवाद किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हुए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य

और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बच्चों से उनके वर्तमान विद्यालय, पढ़ाई की स्थिति और रुचियों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने यह भी जाना कि बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने छात्रवृत्ति की उपलब्धता और शासन द्वारा दी जा रही अन्य सहायता योजनाओं के बारे में भी बच्चों से सीधे जानकारी ली। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीएम केयर्स में लाभान्वित बालक/बालिकाओं को स्पांसरशिप योजना, महतारी दुलार योजना, एक्सग्रेसिया (आपदा प्रबंधन राहत कोष), 23 वर्ष पूर्ण होने पर एकमुश्त 10 लाख रूपए की राशि, कक्षा पहली से 12वीं तक अध्ययनरत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 20 हजार रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सभी बच्चों के आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के वोटर आईडी कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी बच्चों से उनकी वर्तमान पढ़ाई और शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। बच्चों ने अपने-अपने अध्ययन और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान कलेक्टर ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, लक्ष्य निर्धारित करने तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास के अधिकारी अजय साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती प्रीति डांगरे, परियोजना समन्वयक चंद्रप्रकाश पटेल, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कमर्चारी उपस्थित थे।

एसीबी की कार्रवाई : पीएफ निकालने के एवज में 10 हजार रिश्वत लेते सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी गिरफ्तार

दुर्ग। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत तांत्रिक विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी शिव कुमार ठाकुर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विभाग के एक बाबू से उसकी भविष्य निधि की राशि निकालने के एवज में रिश्वत मांगी थी।

बेटी की शादी के लिए चाहिए थी पीएफ की राशि : मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता को बेटी की शादी के लिए तत्काल पीएफ की राशि की जरूरत थी। आरोप है कि शिव कुमार ठाकुर ने पीएफ निकालने के बदले पहले 5 लाख रुपये की मांग की। बाद में सौदेबाजी के बाद 10 हजार रुपये लेने पर सहमति बनी।

रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी : शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने सत्यापन किया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। टीम ने शिव कुमार ठाकुर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

विभाग में मचा हड़कंप : इस कार्रवाई के बाद विद्युत तांत्रिक विभाग में हड़कंप मच गया है। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

'बिजली पैदा करने वाले राज्य में सबसे महंगी बिजली क्यों' : आप का सरकार पर हमला

6 .23% दर वृद्धि वापस लेने की मांग, 16 जुलाई से उग्र आंदोलन की चेतावनी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

आम आदमी पार्टी ने 1 जुलाई से लागू 6.23 प्रतिशत बिजली दर वृद्धि का कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने कहा कि जिस राज्य में बिजली पैदा होती है, वहीं सबसे अधिक दाम वसूलना अन्याय है। दुर्ग कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर आप नेताओं ने दर वृद्धि वापस लेने की मांग की।

'तीन साल में 16.47% बढ़ी दरें': जसप्रीत सिंह

आप के दुर्ग जिला कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष बिजली महंगी की गई है। 2024 में 8.35%, 2025 में 1.89% और 2026 में 6.23% की वृद्धि हुई। तीन वर्षों में कुल 16.47% दरें बढ़ी हैं। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति नहीं मिली और ट्रिपिंग की समस्या भी जस की तस है।

औसत बिलिंग दर भी बढ़ी

विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार औसत बिलिंग दर भी लगातार बढ़ी है। 2024-25 में 6.92 रुपये प्रति यूनिट, 2025-26 में 7.02 रुपये और 2026-27 में 7.13 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। दो वर्षों में प्रति यूनिट औसत दर में 21 पैसे की वृद्धि हुई है।

'घाटे की जांच हो': वदूद आलम

आप के प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कहा कि यदि बिजली कंपनी घाटे में है तो उसके कारणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार बताए कि तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान

आप की प्रमुख मांगें

1. 6.23% बिजली दर वृद्धि तत्काल वापस ली जाए
2. बिजली कंपनी के वित्तीय घाटे की स्वतंत्र जांच कराई जाए
3. जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो
4. बड़े बकायेदारों से लंबित राशि की वसूली हो
5. स्मार्ट मीटरों की तकनीकी जांच हो
6. विवादित बिलों की पुनर्गणना कर राहत दी जाए

स्मार्ट मीटर पर भी सवाल

संगठन मंत्री बलविंदर सिंह ने कहा कि दुर्ग जिले सहित कई जगहों से स्मार्ट मीटरों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। उपभोक्ताओं ने अधिक बिल और रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत की है। पार्टी ने स्मार्ट मीटरों की स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है।

16 जुलाई से उग्र आंदोलन की चेतावनी

पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि 16 जुलाई तक मांगें नहीं मानी गईं तो बिजली कार्यालयों का घेराव, धरना और व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में धर्मेंद्र चौधरी, राउफ अंसारी, सोनू यादव, शिवा श्रेष्ठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। बड़े बकायेदारों से वसूली क्यों नहीं हुई। बिजली चोरी रोकने की जवाबदेही किसकी तय हुई।

राजभाषा कार्यशाला में अधिकारियों व कर्मचारियों ने रखे अपने विचार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में नगर सेवाएँ विभाग ने राजभाषा कार्यशाला के अंतर्गत 'मेरा विषय-मेरी समालोचना' विषय पर हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम नगर सेवाएँ भवन के सभागार में हुआ। इसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के प्रति अनुराग बढ़ाना और कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक सुश्री आर. रंजनी ने की।

समालोचना विकास का आधार: राजीव कुमार

मुख्य अतिथि महाप्रबंधक राजीव कुमार ने संत कबीर के दोहे "निंदक नियरे राखिए" का उल्लेख करते हुए कहा कि समालोचना व्यक्ति और संगठन दोनों के विकास का आधार है। रचनात्मक आलोचना से आत्ममंथन की प्रेरणा मिलती है और कार्यशैली में सकारात्मक सुधार होता है।

नई शिक्षा प्रणाली पर हुई चर्चा

विशिष्ट वक्ता देवेन्द्र कुमार दुबे ने '21वीं शताब्दी की नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जन-जागरण कार्यक्रम' विषय पर विचार रखे। उन्होंने ज्ञानवर्धक साहित्य के अध्ययन, मानसिक विकास और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर जोर दिया। उप प्रबंधक जितेन्द्र दास मानिकपुरी ने समालोचना की अवधारणा और उपयोगिता बताई।

प्रतिभागियों ने रखे विचार

संगोष्ठी में इंजीनियरिंग एसोसिएट आलोक ताम्रकार ने 'अचानक ठप हुए बड़े सिस्टम की दुरुस्ती की प्रक्रिया', डॉ. शीतल चंद्र शर्मा ने '90 के दशक का हिंदी सिनेमा', जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट वाई. उमाशंकर राव ने 'वर्तमान दौर में एआई', सहायक महाप्रबंधक रमेश कुमार गुप्ता ने 'आईना' और सहायक महाप्रबंधक पीएल साहू ने 'मीडिया तंत्र' विषय पर समालोचनात्मक प्रस्तुति दी।

2010 से मिल रहा राजभाषा पुरस्कार

उप प्रबंधक मुकुंद दास मानिकपुरी ने बताया कि नगर सेवाएँ विभाग वर्ष 2010 से राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्यालयीन कार्य के लिए निदेशक प्रभारी 'राजभाषा वैजयंती पुरस्कार' प्राप्त कर रहा है। समापन पर महाप्रबंधक सुश्री आर. रंजनी ने सभी वक्ताओं की सराहना की। प्रतिभागियों और श्रोताओं को सम्मानित किया गया। अतिथियों को स्मृति-चिह्न भेंट किए गए।

डॉक्टर्स डे पर भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ ने 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों का किया सम्मान

अध्यक्ष घनश्याम देवांगन बोले : वरिष्ठजनों के स्वस्थ जीवन में डॉक्टरों की भूमिका अहम

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

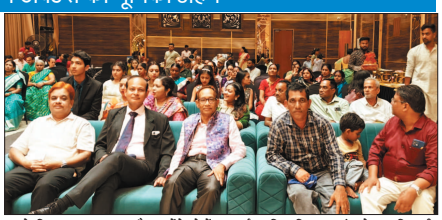

भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के तत्वावधान में "नेशनल डॉक्टर्स डे" के अवसर पर रिवेरा रिसोर्ट में एक गरिमामय समारोह में विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को समाज के प्रति उनके उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा, समर्पण और मानवीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

समारोह की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष घनश्याम कुमार देवांगन ने की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि चिकित्सक केवल रोगों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि समाज को स्वस्थ, सुरक्षित एवं खुशहाल जीवन प्रदान करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण, समय पर उपचार तथा मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण चिकित्सा सेवा में डॉक्टरों का योगदान अत्यंत प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है। ऐसे समर्पित चिकित्सकों का सम्मान करना उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है।

समारोह में सम्मानित होने वाले विशेषज्ञों में डॉ श्रीरंजन राव रेडियोलॉजी, डॉ सुमन राव नेफ्रोलॉजी, डॉ असित नायक कार्डियो एण्ड एनेस्थीसिया, डॉ सुषमा नायक पिडियाट्रिक्स , डॉ स्मिता पटेल मेडिसीन, डॉ यामिनी नायक, डॉ अनय नायक शामिल हैं।

सम्मानित चिकित्सकों ने इस सम्मान के लिए भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वरिष्ठजनों की सेवा करना उनके लिए केवल दायित्व नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय है। अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन शैली नवजात शिशु से लेकर वयोवृद्ध सबके लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने लोगों के द्वारा पूछे गए समस्याओं पर उचित परामर्श एवं अच्छे पैरिस्टिंग पर टिप्स भी दिए।

इस अवसर पर दिनेश कुमार गुप्ता, लोचन प्रसाद नायक, कुसुम नायक, सुमन देवांगन, हिमांशु देवांगन, कल्पना देवांगन, देवी प्रसाद नायक, प्रताप नायक, दिलीप नायक, जयंती नायक, विमल वर्मा, भुवनेश्वर वर्मा, भास्कर वर्मा आदि सहित महासंघ के पदाधिकारी, सदस्यगण, वरिष्ठ नागरिक तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने सम्मानित चिकित्सकों के प्रति अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल चिकित्सा जीवन की कामना की। समारोह का वातावरण आत्मीयता, सम्मान एवं कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत रहा।

एसआर हॉस्पिटल चिखली में केक काटकर धूमधाम से मनाया डॉक्टर्स डे

चेयरमैन संजय तिवारी ने डॉक्टरों व स्टाफ को किया सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और स्टाफ को सम्मानित किया गया। सभी ने मिलकर केक काटा और खुशियां साझा कीं। आयोजन का उद्देश्य समाज में डॉक्टरों के त्याग और सेवा भावना के प्रति सम्मान प्रकट करना था।

'डॉक्टर सेवा और मानवता के प्रतीक' : एसआर हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि डॉक्टर समाज के लिए सेवा, समर्पण और मानवता के प्रतीक हैं। कठिन परिस्थितियों में भी डॉक्टर कर्तव्य निभाते हुए लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। उनका सम्मान करना पूरे समाज का दायित्व है।

डॉ. बीसी राय को किया याद : कार्डियोलॉजी सर्जन डॉ. रंजन सेन गुप्ता ने कहा कि 1 जुलाई को डॉ. बीसी राय का जन्मदिन चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सा पेशा एक परिवार की तरह है जिसमें सभी मिलकर मरीज का इलाज करते हैं। जनरल मेडिसिन के डॉ. केके जैन ने कहा कि डॉ. बीसी राय ने जीवन के आखिरी दिनों तक निःस्वार्थ सेवा दी। उनके सेवाभाव को याद करते हुए डॉक्टर्स डे मनाया गया।

जनरल सर्जन डॉ. वाईके शर्मा और नेत्र विभाग की डॉ. वनश्री सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर्स डे संदेश देता है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ में सेवाभाव होना चाहिए। जिस तरह डॉ. बीसी राय ने अंतिम क्षणों तक सेवा दी, उसी तरह हमें भी निःस्वार्थ होकर सेवा देनी चाहिए। उन्होंने चेयरमैन संजय तिवारी का आभार भी जताया।

डॉक्टरों और स्टाफ का हुआ सम्मान : चेयरमैन संजय तिवारी ने मेडिकल सुप्रीटेंडेंट डॉ. रंजन सेन गुप्ता, डॉ. केके जैन, डॉ. वाईके शर्मा और डॉ. वनश्री सिन्हा को स्मृति चिह्न, उपहार और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इसके अलावा डॉ. दीपा मिश्रा, डॉ. ममता साहू, डॉ. सुमित सोनी, डॉ. बलिराम रॉय, डॉ. अश्वनी शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। बेहतर प्रदर्शन के लिए सीनियर अकाउंटेंट अभिषेक तिवारी, नेत्र विभाग सहायक प्रेम चंद्राकर, आयुष्मान इंचार्ज प्रियेश मिश्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर जगजीत नारायण पांडेय, श्रीमती सीमा बरहरे और श्रीमती तनुजा साहू को सम्मान मिला।

सेवा का दोहराया संकल्प : सम्मान पाकर डॉक्टरों ने आभार जताया और भविष्य में भी पूरी निष्ठा और तत्परता से मरीजों की सेवा करने का संकल्प दोहराया।

लायंस क्लब भिलाई पिनेकल ने पांच महिला चिकित्सकों का किया सम्मान

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर लायंस क्लब भिलाई पिनेकल ने पिनेकल कार्यालय में चिकित्सकों के सम्मान एवं सामान्य सभा का आयोजन किया।

महिला चिकित्सकों का सम्मान : कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली डॉ. वैशाली भगत, डॉ. रीना बनर्जी, डॉ. वनीता राठौड़, डॉ. अनीता भट्टाचार्य और डॉ. दीक्षाली इंदुरकर को शॉल और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।

नेतृत्व और चर्चा : यह आयोजन चार्टर अध्यक्ष लायन विभा भूटानी, पूर्व अध्यक्ष लायन रेविका बेदी, अध्यक्ष लायन शालिनी सोनी तथा कोषाध्यक्ष लायन शुभ्रता नागपाल के नेतृत्व में हुआ। सामान्य सभा में क्लब की आगामी सेवा परियोजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

खेल और अल्पाहार का आयोजन : सम्मान समारोह के बाद सदस्यों ने मनोरंजक खेलों और हाउजी का आनंद लिया। केक काटकर डॉक्टर्स डे का उत्सव मनाया गया। हाई-टी और स्वादिष्ट अल्पाहार की व्यवस्था जुलाई टीम की सदस्य उर्मिला ताओरी, ममता मुंदड़ा, नंदिनी हिवासे और प्रिया राडतोगी ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने में शोभा डोगरा, मंजू अग्रवाल, रश्मि गेडाम, प्राशी तिवारी, उषा चक्रवर्ती, शीना शेखर और अवर्ना झा सहित सभी सदस्याओं का विशेष सहयोग रहा।

सेक्टर-9 अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित, डॉ. बीसी राय को दी पुष्पांजलि, चिकित्सकों का सम्मान

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रख्यात चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों ने उनके व्यक्तित्व और चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण को नमन किया।

स्काफ समारोह में चिकित्सकों का सम्मान

समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार और आईएमए दुर्ग के अध्यक्ष डॉ. रजनीश मल्होत्रा सहित सभी वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। चिकित्सकों के सम्मान में 'स्काफ समारोह' आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन चिकित्सकों के बीच आपसी सहयोग और टीम भावना को मजबूत करते हैं। आईएमए दुर्ग शाखा के सहयोग से ब्लड डोनेशन ड्राइव भी आयोजित की गई। इसमें चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह से स्वैच्छिक रक्तदान किया और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

'चिकित्सा सेवा मानवता का सर्वोच्च माध्यम' : चिकित्सकों ने कहा कि चिकित्सा सेवा केवल पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। उन्होंने रोगियों को गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील और समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प दोहराया। भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस चिकित्सकों के योगदान के प्रति सम्मान और स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

क्या छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक परिवहन सुविधा गुजरात से 50गुना पीछे? जनता की जेब पर पड़ता भारी बोझ

गुजरात राज्य में जनता को सुगम सुलभ और सस्ता सफर दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की जनता की जेब पर पड़ता डाका, दोनों जगह बीजेपी की सरकार

नरेन्द्र डाकलिया / रायपुर-अहमदाबाद

भारत में सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण की बात अक्सर की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य-दर-राज्य इसमें भारी अंतर देखने को मिलता है। हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में BRTS (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) का सफर करने के दौरान नई इष्टिबिंदु के सलाहकार संपादक राजनांदगांव निवासी नरेन्द्र डाकलिया एक यात्री के रूप में जो अनुभव साझा किया है, वह छत्तीसगढ़ की परिवहन व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।

अहमदाबाद में यात्रा के दौरान 'ISKCON Cross Road' से 'Bhavya Park' तक का सफर किया, जिसका किराया मात्र 10 रुपये रहा। इतनी कम कीमत पर वातानुकूलित (एसी) और आरामदायक बस सेवा की सुविधा देखकर यात्री चकित रह गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित है और दफ कोड आधारित टिकट प्रणाली (जैसा कि image में देखा जा सकता है) पर चलती है, जो पारदर्शिता और दक्षता को दर्शाती है।

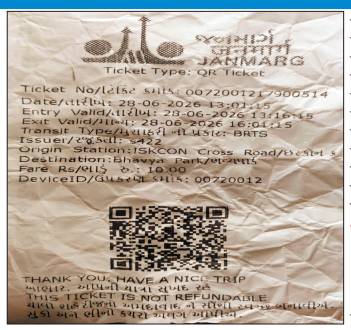

छत्तीसगढ़ की कड़वी हकीकत

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिति पूरी तरह से विपरीत है। यहाँ की जनता आज भी परिवहन के लिए पूरी तरह से प्राइवेट बसों, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर निर्भर है। सरकार की ओर से कोई भी संगठित या किफायती सार्वजनिक परिवहन तंत्र न होने के कारण, आम आदमी को इन प्राइवेट ऑपरेटरों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलना एक आम बात हो गई है, जिससे एक आम नागरिक की दैनिक आय का एक बड़ा हिस्सा केवल आने-जाने के खर्च में निकल जाता है।

व्यवस्था में चूक या इच्छाशक्ति की कमी?

नागरिकों का मानना है कि यदि गुजरात जैसा राज्य अपने नागरिकों को मात्र 5 से 10 रुपये में अंड बस में सुरक्षित और सम्मानजनक सफर दे सकता है, तो छत्तीसगढ़ में यह क्यों संभव नहीं है? विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में परिवहन का ढांचा दशकों से वैसा ही बना हुआ है। सरकार की ओर से आधुनिक बस सेवा उपलब्ध न कराना सीधे तौर पर जनता पर आर्थिक बोझ डालना है। प्राइवेट बसों के अनियंत्रित रेट और ऑटो चालकों की 'लूट' को सरकार का संरक्षण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार खुद विकल्प प्रदान करने में नाकाम रही है।

बदलाव की मांग

अहमदाबाद की इस सुखद यात्रा देखने के बाद छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार निवासी के रूप में अब छत्तीसगढ़ के लिये यह मांग उठाई जा रही है कि छत्तीसगढ़ शासन को भी गुजरात के मॉडल का अध्ययन करना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ के नागरिक भी कभी ऐसी सुविधा की उम्मीद कर सकते हैं? यह केवल एक परिवहन की सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों और सुशासन का भी मुद्दा है। यदि सरकार चाहती है कि आम आदमी का जीवन स्तर सुधरे, तो उसे तुरंत आधुनिक और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। क्या जनता को हमेशा ऐसे ही प्राइवेट ऑपरेटरों के भरोसे लूटा जाता रहेगा, या सरकार अपनी जवाबदेही समझेगी? यह प्रश्न आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक आम नागरिक के मन में उठाना चाहिए ।

खास खबर

'बिना सहकार, कृषि का नहीं उद्धार' : डॉ. रमन के कार्यकाल में सुधरी सहकारी समितियों की हालत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

भाजपा किसान नेता अशोक चौधरी बोले, गुजरात-महाराष्ट्र की तरह दुग्ध क्षेत्र में भी बढ़ाना होगा सहकार

भाजपा किसान नेता अशोक चौधरी ने कहा कि भारत में सहकारी संस्थाएं आंदोलन के रूप में शुरू हुई थीं। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सहकारी संस्थान सबसे सफलता से संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है और सरकार किसानों की चिंता कर रही है।

डॉ. रमन के कार्यकाल में सुधरी स्थिति : अशोक चौधरी ने बताया कि जब डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री के पद पर थे तब सहकारी संस्थाओं की हालत बहुत खराब थी। कई संस्थाएं डिफाल्टर श्रेणी में थीं। डॉ. रमन ने धान खरीदी की व्यवस्था सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नई नीति बनाकर की। इसमें धान का बोरा, सिलाई की रस्सी, तौलने और बोरा भराई के लिए मजदूर, सबकी अलग-अलग राशि सोसाइटियों को उपलब्ध कराई जाने लगी।

आर्थिक रुप से मजबूत हुई समितियां : चौधरी ने कहा कि नई नीति से सहकारी साख समितियों की आर्थिक हालत सुधरी। कृषि उपज समितियों को धान खरीदी पर शुल्क मिलने लगा। इससे आज छत्तीसगढ़ की सहकारी साख समितियों की आर्थिक हालत सुदृढ़ है। उन्होंने कहा कि आज हम कह सकते हैं कि बिना सहकार, कृषि का नहीं उद्धार।

दुग्ध क्षेत्र में भी सहकारिता बढ़ाने की जरुरत : किसान नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता केवल कृषि में दिखाई देती है। अभी दुग्ध और अन्य क्षेत्रों में गुजरात और महाराष्ट्र की तरह काम करने की आवश्यकता है। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, इसका उदाहरण सहकारिता सप्ताह के आयोजन से मिल रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से राजनांदगांव का साहू परिवार बना ऊर्जा आत्मनिर्भर

रायपुर। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को नई गति दे रही है। राजनांदगांव जिले के ग्राम गढ़ुला का साहू परिवार इस योजना का लाभ लेकर न केवल अपना बिजली बिल शून्य करने में सफल हुआ है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की प्रेरक मिसाल भी बन गया है। ग्राम गढ़ुला में टीकम होटल का संचालन करने वाले अंकालु राम साहू और उनके पुत्र कुंदन साहू ने अपने घर पर 3-3 किलोवाट क्षमता के दो सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए। होटल व्यवसाय के कारण प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपये तक का बिजली बिल आता था, जिसे कम करने के लिए उन्होंने सौर ऊर्जा को अपनाया।

साहू परिवार ने योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया। दोनों प्लांटों की कुल लागत लगभग 4 लाख रुपये रही, जिसमें केंद्र एवं राज्य शासन से कुल 2 लाख 16 हजार रुपये की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में प्राप्त हुई। इससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आई। सोलर प्लांट शुरू होने के बाद परिवार का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत अतिरिक्त उत्पादित बिजली ग्रिड में भेजी जा रही है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त आय की भी संभावना बनी है। अब साहू परिवार केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादक भी बन गया है।

साहू परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम नागरिकों के लिए आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आकर्षक सब्सिडी के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक परिवार स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा से जुड़ रहे हैं।

पत्रकार रविकांत सिंह राजपूत को मिलेगा देश का प्रतिष्ठित 'समाचार 4 मीडिया 40 अंडर 40 अवॉर्ड

28 जुलाई को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगी देश की दिग्गज मीडिया हस्तियों की महफिल

नई दृष्टिबिंदु / मनेन्द्रगढ़

पत्रकारिता जब समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने के साथ-साथ व्यवस्था को बदलने का जज्बा रखती हो, तो सम्मान राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर खुद-ब-खुद कदम चूम लेता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ऊर्जावान और निर्भीक पत्रकार रविकांत सिंह राजपूत ने। समाचार 4 मीडिया द्वारा आयोजित देश के सबसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 अवॉर्ड्स के चौथे संस्करण के विजेताओं में रविकांत का चयन किया गया है। आगामी 28 जुलाई 2026 को देश की राजधानी नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले एक भव्य और गरिमामयी समारोह में उन्हें इस राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। इस गौरवशाली उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ और पत्रकारिता जगत का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है।

कड़े मानकों और दिग्गज जूरी की कसौटी पर उतरे खरे

समाचार 4 मीडिया 40 अंडर 40 मीडिया जगत का एक ऐसा सम्मान है, जिसके अंतर्गत प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया से जुड़े देश भर के 40 वर्ष से कम आयु के उन चुनिंदा और प्रभावशाली पत्रकारों को चुना जाता है, जिन्होंने अपने साहसिक कार्यों, बेजोड़ नेतृत्व क्षमता और पत्रकारिता के प्रति अटूट समर्पण के बल पर एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस वर्ष विजेताओं का चयन देश के शीर्ष संपादकों, मीडिया विशेषज्ञों और वरिष्ठ हस्तियों की एक उच्च स्तरीय जूरी द्वारा बेहद कड़े और सूक्ष्म मानकों के आधार पर किया गया, जिसमें रविकांत सिंह राजपूत ने अपनी धारदार ग्राउंड रिपोर्टिंग के दम पर देश के टॉप-40 में अपनी जगह पक्की की।

दिल्ली में जुटेगा भारतीय मीडिया का शीर्ष नेतृत्व

रविकांत को यह सम्मान 28 जुलाई 2026 को शाम 5:00 बजे से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सेमिनार हॉल में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इस भव्य अवॉर्ड नाइट से पहले सुबह 10:00 बजे से एक विशेष मीडिया कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने-माने और दिग्गज संपादक व वरिष्ठ पत्रकार विभिन्न महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर मंथन करेंगे। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए भारतीय मीडिया जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं।

पहले मिल चुका है यूनिसेफ अवॉर्ड

रविकांत सिंह राजपूत की यह सफलता उनकी लगातार की जा रही गंभीर, खोजी और सरोकार की पत्रकारिता का जीवंत प्रमाण है। गौरतलब है कि इससे पूर्व रविकांत को बच्चों के अधिकारों, ग्रामीण शिक्षा और उनके संवेदनशील मुद्दों पर अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उत्कृष्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ का प्रतिष्ठित 'मीडिया 4 चिल्ड्रन अवॉर्ड भी मिल चुका है।

सुदूर वनांचल अंचलों में अंधविश्वास के कारण बंद पड़े स्कूलों का ताला खुलवाना हो, या शोषितों-वंचितों की समस्याओं को शासन-प्रशासन के गलियारों तक पहुंचाकर उनका समाधान करवाना हो, रविकांत ने हमेशा पत्रकारिता के मूल्यों को सर्वोपरि रखा है। यूनिसेफ के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर '40 अंडर 40' की फेहरिस्त में शामिल होना उनके पत्रकारिता करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ता है।

यूनिसेफ के बाद अब समाचार 4 मीडिया का यह राष्ट्रीय सम्मान मिलना मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है। यह पुरस्कार उन सभी आम लोगों की उम्मीदों और संघर्षों को समर्पित है, जिनकी आवाज को मैंने मंच देने का प्रयास किया। मीडिया जगत के वरिष्ठों के मार्गदर्शन और जिले के साथी पत्रकारों व प्रबुद्धजनों के सहयोग के बिना यह सफर संभव नहीं था।

शालिनी पटेल भगवा पार्टी भिलाई शहर अध्यक्ष ने किया शहर कोर कमेटी का गठन

मनोज, डॉ. प्रभा, अनीश चौबे बने उपाध्यक्ष, महासचिव संजय मिश्रा एवं डॉ.आशीष जैन को मिली कोषाध्यक्ष पद की जवाबदारी

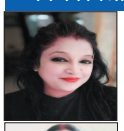

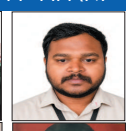

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शालिनी पटेल भगवा पार्टी भिलाई शहर अध्यक्ष ने शहर कार्यकारिणी में कोर कमेटी में नियुक्तियां की है। जिसमें भिलाई शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज घोड़ेसवार, उपाध्यक्ष डॉ प्रभा पटेरिया, अनीश चौबे, महासचिव संजय मिश्रा, रामेन्द्र नेताम, कोषाध्यक्ष डॉ आशीष जैन, सचिव पूनम पटेल, रूबी कुमारी, तारा झा, कवलजीत कौर, ललित शुक्ला, टिकेश्वर वैष्णव, प्रीति साव, देवव्रत कुमार एवं कार्यकारिणी सदस्य श्रुति पटेल, आयुष मिश्रा, के व्यंकटेश्वर, वीरेंद्र कुमार, सुनील साहू, मनीष सोनी, सर्वेश भट्ट, मोहिनी साहू, जीतेन्द्र कुमार जंघेल, उमा साहू, रीतेश बंजारे, रूबी झा, तारा चरण झा, परमजीत कौर नियुक्त किये गए है। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला के मंशानुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष देवेश मिश्रा की अनुमति व प्रदेश महासचिव ज्ञानेश्वर प्रसाद ताम्रकार भगवा पार्टी छत्तीसगढ़ की अनुशंसा से की गई है।

प्रदेश अध्यक्ष देवेश मिश्रा ने अध्यक्ष शालिनी पटेल एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि सभी पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से भगवा (भारतीय गण वार्ता) पार्टी के उद्देश्यों, रीति नीति व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने, पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं जन कल्याण हेतु कार्य प्रारम्भ कर दें। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति पर प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष अतुल नंद शुक्ला, हिरेन्द्र कुमार साहू, महासचिव ज्ञानेश्वर प्रसाद ताम्रकार, आकाश दुबे, प्रदेश सचिव मीना बिष्ट एवं वरुणेश्वर पाण्डेय, विपिन गुप्ता, प्रियंक सोनी, मनहरण साहू, भागवत देवांगन, ओमप्रकाश सोनी, मनोज गुप्ता, मेघराज कोटवानी ने बधाई दी है।

कलेक्टर ने रायपुर निगम के 11 नव नामांकित पार्षद एल्डरमेन को पद की दिलाई शपथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर नगर पालिक निगम में 11 नामांकित पार्षद एल्डरमेन रामकिंकर सिंह, विनय ओझा, मनीष करडभुजे, मित्रसेन धीमान, राजू राघवानी, गोपाल सोना, बी. निवास राव, अनिल सोनकर, गोपी साहू, विक्रम सिंह ठाकुर, ऋषि साहू को रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने रायपुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पद की शपथ दिलवाई। सभी 11 नामांकित पार्षदो, एल्डरमेनो ने पद की ईश्वर के नाम सत्यनिष्ठा की शपथ ली। इस अवसर पर रायपुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, नगर निगम आयुक्त सबित मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक प्रतिनिधि मैकमिलन साहू, रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर सहित नगर निगम रायपुर के एमआईसी सदस्यो, पार्षदो, निगम अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय, निगम सचिव सगीता साहू की उपस्थिति रही।

जनदर्शन में मंत्री अग्रवाल ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड लखनपुर की ग्राम पंचायत परसोंडी पहुंचकर ग्रामीणजनों से आत्मीय भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्होंने पेयजल, सड़क, विद्युत, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े विषय मंत्री श्री अग्रवाल के समक्ष रखे। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से चर्चा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों से संवाद करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है, जहां आम नागरिक अपनी बात सीधे रख सकता है और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास के संकल्प को साकार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री राजेश अग्रवाल के सहज, सरल एवं संवेदनशील व्यवहार की सराहना करते हुए अपनी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनके समाधान के लिए त्वरित पहल करने पर आभार व्यक्त किया। जनदर्शन के इस कार्यक्रम ने शासन और आमजन के बीच संवाद, विश्वास और सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ करने का कार्य किया।

कॉलेजों में बहेगी विकास की बयार, 700 प्राध्यापकों की भर्ती के साथ खुलेंगे तरक्की के द्वार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प और युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को नया कलेवर देने और सालों से अटके प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए आज उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए।

प्रदेश के उच्च शिक्षा इतिहास में युवाओं के लिए इसे सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है। बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मंत्री टंक राम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई रुकावट या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी

शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। सीजीपीएससी के माध्यम से होने वाली प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

महाविद्यालयों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। न्यू शिक्षा सत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी स्नातक कॉलेज बिना नियमित प्राचार्य के नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के एजेंडे में "शिक्षा की गुणवत्ता" सबसे ऊपर है।

पदोन्नति का रास्ता साफ, कर्मचारियों और अतिथि प्राध्यापकों की सुनी गई मांग : प्राध्यापकों और विभागीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैठक में कई संवेदनशील निर्णय लिए गए। ?पुराने नियम से मिलेगी तरक्की साल 2019 से पहले के बचे हुए सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां लगभग तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से संघर्षरत अतिथि प्राध्यापकों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार तुरंत एक्शन लेने जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब 'राज्य कर्मचारी चयन आयोग' के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

ग्रामीण और आदिवासी अंचल के छात्र अब फर्राटेदार बोलेंगे अंग्रेजी : राज्य सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के होनहारों के लिए एक अनोखी पहल की है। अब महाविद्यालयों में "90 घंटे, 90 दिन" का विशेष अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स चलाया जाएगा। इस अनूठे अभियान से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के भीतर का संकोच दूर होगा और वे देश-दुनिया के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला सकेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में शासन के शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सुस्त कार्यप्रणाली पर बरसे मंत्री : '31 जुलाई तक हर हाल में दें स्नातक कॉलेजों को नए प्राचार्य'

वित्तीय अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस: बजट आवंटन में कोई पक्षपात नहीं बजट प्रबंधन को लेकर मंत्री श्री वर्मा ने वित्तीय शुचिता का संदेश देते हुए कहा कि विभाग में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। अब किसी भी कॉलेज को बजट जारी करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। नए महाविद्यालयों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ताकि किसी भी संस्थान को कम या ज्यादा राशि मिलने की शिकायत का मौका न मिले।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अब स्नातकोत्तर में भी होगा विस्तार : छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 साल के सफल स्नातक पाठ्यक्रम के बाद अब स्नातकोत्तर को भी एन.ई.पी. के दायरे में लाने की मुकम्मल तैयारी शुरू हो गई है। वर्तमान में एन.ई.पी. के 5वें और 6वें सेमेस्टर के लिए केंद्रीय अध्ययन मंडल की सूची को अंतिम रूप देकर लोक भवन की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 'अपर संचालक' के पद को 'प्राचार्य' के पद से पूरी तरह अलग करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, प्राचार्यों के कार्यकाल का ऑडिट करने के लिए प्रदेश के लेखा उत्तीर्ण कर्मचारियों की विशेष सेवाएं ली जाएंगी, जिससे लंबित जांच और ऑडिट के मामलों का तुरंत निपटारा हो सके। इस बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त सहित मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।

संपादकीय

लेने वाली नहीं देने वाली सरकार अच्छी मानी जाती है

हर चीज की अपनी कीमत होती है।उसे पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पाना होता है,वह जानते हैं कि सत्ता की अपनी कीमत होती है। सत्ता पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सत्ता कोई बाजार में बिकती तो नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वह ज्यादा पैसा देकर सत्ता खरीद ले।सत्ता तो उसे मिलती है जिसे ज्यादा संख्या में लोग वोट देते हैं।जिसे ज्यादा वोट जनता ने दे दिया सत्ता उसकी गई जिसे ज्यादा वोट नहीं मिले सत्ता उसे नहीं मिलती। सत्ता का सीधा संबंध ज्यादा वोट से होता है, इसलिए राजनीतिक दल कई तरह के वादे करते है, कई तरह के उपाय करते हैं ताकि जनता उनको दूसरे राजनीतिक दलों से ज्यादा वोट दे और सत्ता उसे मिल सके।राजनीतिक दलों के यह जो वादे होते हैं, वह एक तरह से सत्ता की कीमत होती है।जो जितना ज्यादा देने का वादा करता है, मतलब यही होता है कि वह सत्ता की ज्यादा कीमत देने को तैयार है। जो ज्यादा से ज्यादा देता है, वह सत्ता की ज्यादा से ज्यादा कीमत देता है या देने को तैयार रहता है।तो अच्छी सरकार वही मानी जाती है जो चुनाव में ज्यादा देने का वादा करती है और सरकार बनने के बाद देती भी है।

साय सरकार बने दो साल हो गए हैं और दो साल में सरकार ने चुनाव में किए वादे पूरे किए है और हर महीने कई वादे पूरे कर रही है इसके अलावा सरकार में आने के बाद विकास के कई काम करने होते है, जनहित के कई काम करने होते है, राज्यहित में कई काम करने होते हैं। इससे राज्य का खर्च बढ़ता है। राज्य का खर्च बढ़ाता है तो आय बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है।वैसे तो राज्य सरकारों की कोशिश होती है कि कर्ज लेकर जनता पर कोई बोझ न डाला जाए और जनता की कसौटी पर देने वाली सरकार की छबि बनी रहे। लेकिन कई बार जनता पर बोझ डालना जरूरी हो जाता है। जनता से कई तरीकों से पैसा लेना जरूरी हो जाता है तो सरकार को जनता से पैसा लेना पड़ता है। बिजली की दर बढ़ाना भी इसी तरह का प्रयास है जब भी बिजली दर बढ़ाना जरूरी हो जाता है तो सरकार बिजली दर बढ़ाती है। इसी के साथ उसकी कोशिश रहती है कि लोगों पर बोझ कम से कम पड़े। साय सरकार इस मामले में संवेदनशील है। वह जानती है कि बिजली दर बढ़ने से जनता पर बोझ बढ़ता है और उसका बजट बिगड़ता है वह नाराज होती है।यही वजह है कि वह जनता को बताती है कि वह बिजली दर बढ़ाने को मजबूर है लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में बिजली दूसरे राज्यों की तुलना में सस्ती है।

सरकार ने हाल ही में बिजली दर को बढ़ाया है और कहा है कि इसका प्रभाव विभिन्न श्रेणियों मे दी जा रही रियायतों के कारण सीमित रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक बिजली दर बढ़ने से 100 यूनिट तक 30 पैसे तो 600 यूनिट से अधिक पर 70 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा बिजली के मामले में सरकार की कोशिश यही रहती है कि उसकी छबि पिछली सरकार की तुलना मे अच्छी बनी रहे ।पिछली सरकार के समय सभी लोगों को बिजली हाफ योजना के तरह 400 यूनिट बिजली पर 200 यूनिट का पैसा देना पड़ता था इससे लोगों को बिजली के मामले में पैसों की बचत होती थी। साय सरकार ने इस योजना को बंद नहीं किया। क्योंकि वह जानती है कि इस योजना को बंद करने पर जनता नाराज होगी और सरकार की देने वाली छबि खराब होगी और पिछली सरकार से उनकी सरकार बुरा समझा जाएगा। इस योजना का लाभ बाद मे सीमित किया गया। अब पहले से कम लोगों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता है। लेकिन साय सरकार बिजली के मामले में पिछली सरकार की तरह पैसे लेने वाली नहीं पैसे देने वाली सरकार बनी रहना चाहती है इसलिए जनता को इस बात का एहसास करती रहती है वह भी जनता को राहत रियायत देने वाली सरकार है।

बिजली दर बढ़ने के बाद सरकार ने जनता को राहत देने के लिए सरचार्ज में सुधार किया है ।पहले यह होता था कि बिजली बिल पटाने के एक तय तारीख होती थी जो लोग तय तारीख तक बिजली बिल पटा देते थे उनको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ता था इसके बाद किसी कारण से कोई एक दो दिन देरी से बिजली बिल पटाता था तो उसे महीने भर का सरचार्ज पटाना पड़ता था। साय सरकार ने इस मामले में अब जनता को राहत देने के लिए यह व्यवस्था की है बिजली बिल पटाने में जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का ही सरचार्ज देना होगा। इससे लोगों के कुछ पैसे बचेंगे ही। इससे भले ही कम पैसे बचें लेकिन सरकार लोगों को यह एहसास दिलना चाहती है कि वह जनता को राहत पहुंचाना चाहती है जैसे भी हो राहत पहुंचाती है। साय सरकार ने मुख्यमंत्री समाधान योजना के जरिए भी राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है।

यह योजना सरकार ने उन लोगों के लिए बनाई है जो बकाया बिजली बिल पटा नहीं पा रहे थे और बिजली बिल बढ़ता जा रहा था इस योजना का लाभ घरेलू, बीपीएल, कृषि सहित बड़े बकायादारों को मिला है इस योजना के तहत सरचार्ज माफ कर दिए जाने के कारण बिजली बिल कम हो जाता है और लोगों को उतना बिल पटाना कठिन नहीं लगता है। यही वजह है समाधान योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 898562 बकायादारों पर बिजली विभाग का 1363.87 करोड़ रुपए बकाया था। सरकार ने अब तक बकायादारों का 700 करोड़ रुपए का बकाया माफ कर दिया है और बिजली विभाग को 72 करोड़ रुपए मिला है। समाधान योजना से बकायादारों को जहां 700 करोड़ का फायदा हुआ है वहीं बिजली विभाग को 72 करोड़ रुपए फायदा हुआ है क्योंकि यह वह पैसा है जो मिलता ही नहीं।इससे सरकार की छबि लेने वाली नहीं देने वाली सरकार की बनी हुई है।

अयोध्या राम मंदिर प्रकरण : कार्यप्रणाली और पारदर्शिता का प्रश्न

महेन्द्र तिवारी

अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा अर्पित करता है। यही कारण है कि जब चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोप सामने आए तो यह मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा। इसने धार्मिक संस्थानों की वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर व्यापक बहस शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में विशेष जांच दल की कार्रवाई ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। विभिन्न समाचार रिपोर्टों के अनुसार जांच अब केवल कथित चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि चढ़ावे की गिनती और जमा करने की जो व्यवस्था तय थी, उसका पालन वास्तव में हुआ या नहीं।

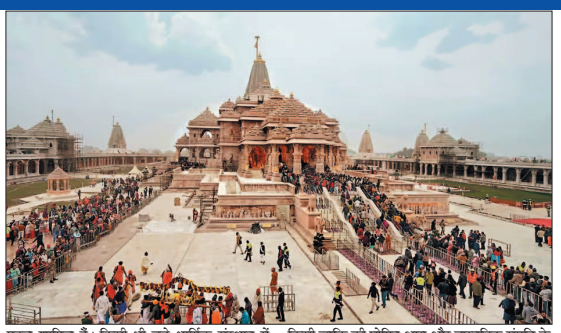

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि चढ़ावे की गिनती के लिए मंदिर ट्रस्ट और बैंक के बीच एक निर्धारित व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नकदी की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी एक व्यक्ति या समूह के भरोसे पूरी प्रक्रिया न रहे। बताया जा रहा है कि गिनती के समय दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त उपस्थिति आवश्यक थी। यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो यह केवल व्यक्तिगत लापरवाही का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था की कमजोरी भी सामने आएगी।

जांच एजेंसियां केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार बैंक अभिलेख, लेनदेन का विवरण, अभिलेखों का मिलान, संबंधित कर्मचारियों की भूमिका और अन्य वित्तीय पहलुओं की भी गहन पड़ताल की जा रही है। यदि किसी व्यवस्था में कई स्तरों पर निगरानी हो और उसके बावजूद कथित अनियमितता सामने आए तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि नियंत्रण तंत्र किस स्तर पर कमजोर पड़ा। यही कारण है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती से जुड़े कई संचालन संबंधी नियमों की समीक्षा की जा रही है। इनमें निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों का नियमित परिवर्तन, निर्धारित पहचान व्यवस्था, अभिलेखों का सुरक्षित रखरखाव और पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही जैसे पहलू शामिल हैं। किसी भी बड़े धार्मिक संस्थान में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में नकदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसलिए ऐसी संस्थाओं में केवल ईमानदारी पर्याप्त नहीं होती बल्कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक होती है।

विशेष जांच दल की कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि मामला केवल अनुमान के आधार पर नहीं चल रहा है। उपलब्ध समाचारों के अनुसार कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसियां संभावित भूमिका निभाने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति की अंतिम जिम्मेदारी या दोष का निर्धारण केवल न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही माना जाएगा।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धार्मिक संस्थानों में आने वाला धन सामान्य सरकारी राजस्व नहीं होता। यह सीधे श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा होता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चढ़ावा देता है और उसे विश्वास होता है कि उसका योगदान उसी उद्देश्य के लिए उपयोग होगा जिसके लिए वह अर्पित किया गया है। यदि इस विश्वास पर प्रश्नचिह्न लगता है तो उसका प्रभाव केवल संबंधित संस्था तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यापक सामाजिक विश्वास पर भी पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांच में वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति की घोषित आय और वास्तविक संपत्ति के बीच असामान्य अंतर पाया जाता है तो जांच एजेंसियां उस पहलू को भी जांच के दायरे में ले सकती हैं। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं हुआ है और जांच जारी है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न भी खड़ा किया है। किसी भी संस्था में नियम केवल कागज पर लिखे रहने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका उद्देश्य जोखिम को कम करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। यदि संयुक्त उपस्थिति, अभिलेख सत्यापन, निगरानी और नियमित निरीक्षण जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जांच एजेंसियां केवल यह नहीं देखतीं कि कथित चोरी किसने की, बल्कि यह भी देखती हैं कि उसे रोकने वाली व्यवस्था क्यों असफल हुई।

देश के अनेक बड़े मंदिरों में अब आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले निगरानी उपकरण, डिजिटल अभिलेख, स्वचालित गिनती प्रणाली और बहुस्तरीय सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। ऐसे में यदि किसी स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होता तो यह प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर विषय बन जाता है।

मामले ने राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न की है। विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच, स्वतंत्र लेखा परीक्षण और पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। दूसरी ओर जांच एजेंसियां अपने स्तर पर साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक बयान और कानूनी जांच को अलग-अलग दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। अंतिम सत्य केवल साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आता है।

रिपोर्टों के अनुसार इस प्रकरण के बीच ट्रस्ट स्तर पर भी महत्वपूर्ण बैठकों की तैयारी की गई है। इन बैठकों में प्रशासनिक ढांचे, भविष्य की कार्यप्रणाली और आवश्यक सुधारों पर विचार होने की संभावना जताई गई है। यदि ऐसा होता है तो यह केवल वर्तमान विवाद का समाधान नहीं होगा बल्कि भविष्य में ऐसी आशंकाओं को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

इस मामले से एक व्यापक सीख भी मिलती है। किसी भी संस्था की विश्वसनीयता केवल उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसकी कार्यप्रणाली से भी तय होती है। जितनी बड़ी संस्था होगी, उतनी ही मजबूत उसकी वित्तीय व्यवस्था और आंतरिक निगरानी होनी चाहिए। पारदर्शिता केवल आरोपों का उत्तर नहीं देते बल्कि भविष्य के विवादों को भी रोकती है।

जांच अभी जारी है और इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। यह संभव है कि जांच के अंत में कुछ आरोप सही सिद्ध हों, कुछ गलत साबित हों और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियागत कमियां सामने आएं। इसलिए वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित हो। किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी या निर्दोष मानने का अधिकार अंततः न्यायिक प्रक्रिया का ही है।

अंततः यह पूरा प्रकरण केवल एक मंदिर या एक संस्था का विषय नहीं है। यह उन सिद्धांतों की परीक्षा भी है जिन पर सार्वजनिक विश्वास टिका होता है। जब करोड़ों लोगों की आस्था किसी स्थान से जुड़ी हो तो वहां पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत नियंत्रण व्यवस्था केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। यदि जांच निष्पक्ष रूप से पूरी होती है और उसके आधार पर आवश्यक सुधार लागू किए जाते हैं तो यह घटना भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकती है। वहीं यदि केवल आरोप और प्रत्यारोप तक मामला सीमित रह गया तो व्यवस्था में सुधार का अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए पूरे देश की निगाहें अब इस बात पर हैं कि विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है और उसके आधार पर संबंधित संस्थाएं पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाती हैं।

जहाँ नाक बंद होती है, वहीं स्वच्छ भारत के दावे खुल जाते हैं

आरके जैन

स्वच्छता किसी राष्ट्र का श्रृंगार नहीं, उसका चरित्र है। किसी देश की असली पहचान संसद, मेट्रो या एक्सप्रेस-वे नहीं, बल्कि वह सार्वजनिक शौचालय है जहाँ सामान्य नागरिक बिना भय, घृणा या नाक सिकोड़े प्रवेश कर सके। पिछले एक दशक में स्वच्छ भारत मिशन जनांदोलन और विकास का प्रतीक बना, लेकिन बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों, पार्कों और राजमार्गों के अधिकांश सरकारी शौचालय इस दावे की सबसे कड़वी सच्चाई हैं। वहाँ प्रवेश करते ही पहले नाक, फिर आँखें बंद करनी पड़ती हैं। यह केवल दुर्गंध नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता है जिसने शौचालय बनाना उपलब्धि माना, पर उन्हें स्वच्छ रखना जिम्मेदारी नहीं समझा। स्वच्छ भारत अभियान की असली परीक्षा सार्वजनिक शौचालयों में होती है, और सबसे बड़ी विफलता भी वहीं दिखाई देती है।

यह कहना अन्याय होगा कि स्वच्छ भारत मिशन ने कुछ नहीं किया। इसकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। 2014 में ग्रामीण भारत में शौचालय कवरेज लगभग 39 प्रतिशत था, जो अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार 95 प्रतिशत से अधिक हो गया है।12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बने, 6 लाख से अधिक गाँव और हजारों शहर ओडीएफ घोषित हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बेहतर स्वच्छता से डायरिया से होने वाली मौतें घटीं और लाखों परिवारों का स्वास्थ्य व्यय कम हुआ। यह निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या स्वच्छता घर की चौखट पर ही समाप्त हो जाती है? क्या घर से बाहर निकलते ही नागरिक की गरिमा अप्रासंगिक हो जाती है? घरों में शौचालय बनाकर आधी लड़ाई जीती गई, मगर सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली ने इस सफलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया।

यही वह विरोधाभास है जो स्वच्छ भारत मिशन की चमक फीकी कर देता है। जनाग्रह और अन्य संस्थाओं के सर्वे बताते हैं कि बड़े शहरों के अधिकांश सार्वजनिक शौचालय भी पानी, नियमित सफाई, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई महीनों से बंद पड़े हैं, कई जर्जर हो चुके हैं और अनेक ठेकेदारों की लापरवाही व प्रशासनिक उदासीनता के कारण उपयोग योग्य नहीं बचे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गों के शौचालय यात्रियों की मजबूरी हैं, सुविधा नहीं। यह संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उस सरकारी सोच का परिणाम है जो शौचालय के उद्घाटन को उपलब्धि मानती है, रखरखाव को नहीं। शौचालय बनते हैं, फीते कटते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं, रिपोर्टें बनती हैं और फिर वे धीरे-धीरे गंदगी के हवाले कर दिए जाते हैं।

सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली की सबसे बड़ी कीमत महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग चुकाते हैं। महिलाएँ प्यास से नहीं, उपयोग योग्य शौचालयों के अभाव में घंटों पानी पीने से बचती हैं। लंबी यात्राएँ उनके लिए सुविधा नहीं, चिंता बन जाती हैं। गंदे शौचालय डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस-ए सहित अनेक संक्रामक रोगों के केंद्र हैं। विद्यालयों में शौचालयों की कमी और बदहाली के कारण कई लाख लड़कियाँ पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं।हालिया रिपोर्टों के अनुसार देश में लगभग 98,500 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए कार्यरत शौचालय नहीं हैं। यह केवल शिक्षा नहीं, महिला सम्मान और सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। अधिकांश सार्वजनिक शौचालय आज भी दिव्यांगों के लिए अनुपयोगी हैं। यदि स्वच्छता ही गरिमा है, तो उनकी यह स्थिति हर दिन करोड़ों भारतीयों की गरिमा को ठेस पहुँचा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत आस्पिरेशनल टॉयलेट योजना शुरू की गई है। करीब 29 हजार आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कई स्थानों पर परियोजनाएँ अभी अधूरी हैं या रखरखाव की कमी के कारण जल्द खराब हो रही हैं। कहीं परियोजनाएँ अधूरी रहीं, तो वने शौचालय भी रखरखाव के अभाव में जल्द बदहाल हो गए।वजह वही पुरानी है—बजट निर्माण के लिए है, रखरखाव के लिए नहीं; जिम्मेदारी सबकी, जवाबदेही किसी की नहीं। नगर निगम ठेकेदार को, ठेकेदार विभाग को और विभाग बजट को दोष देता है। सार्वजनिक संपत्ति को यह मेरी नहीं मानने की मानसिकता भी गंदगी बढ़ाती है। नतीजा, सार्वजनिक शौचालय उपेक्षा के स्मारक बन जाते हैं।

फिर भी तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है।2022 के डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ आंकड़ों के अनुसार देश में अभी भी करीब 15.7 करोड़ लोग (लगभग 11%) खुले में शौच करते थे, जो बताता है कि यात्रियों और अस्थायी आबादी के लिए पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय अब भी उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर, इंदौर, सूरत और कुछ अन्य शहरों ने साबित किया है कि इच्छाशक्ति, नियमित सफाई, चौबीसों घंटे पानी, तकनीकी निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेह प्रबंधन से सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और सम्मानजनक बनाए जा सकते हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएँ और निजी कंपनियाँ भी पे एंड यूज मॉडल से इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। संदेश स्पष्ट है—समस्या संसाधनों की नहीं, प्राथमिकताओं, प्रबंधन और जवाबदेही की है।

अब समय शौचालयों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता से सफलता मापने का है। हर सार्वजनिक शौचालय के लिए पृथक रखरखाव बजट, डिजिटल निगरानी, सीसीटीवी, सोलर पावर, वेस्ट रिसाइक्लिंग, चौबीसों घंटे पानी और नियमित सफाई अनिवार्य हों। महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन हर परियोजना का हिस्सा बने। ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो तथा नियमित ऑडिट, दंड और समीक्षा व्यवस्था लागू हो। स्थानीय समुदाय को निगरानी में भागीदार बनाया जाए और स्वच्छता मेरी जिम्मेदारी को अभियान नहीं, नागरिक संस्कार बनाया जाए। आखिर, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय केवल सरकार की नहीं, सभ्य समाज की भी पहचान हैं।

आखिरकार, किसी राष्ट्र की स्वच्छता का असली पैमाना घरों के नहीं, सार्वजनिक शौचालय हैं। जिस दिन कोई नागरिक रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार या पार्क के शौचालय में बिना भय, घृणा या साँस रोके प्रवेश कर सकेगा, उसी दिन स्वच्छ भारत मिशन अपनी मंज़िल पर पहुँचेगा। तब तक चमकते आँकड़े सरकारी रिपोर्टों की शोभा बढ़ा सकते हैं, जनता का विश्वास नहीं। अब स्वच्छता को अभियान नहीं, संस्कृति और निर्माण को नहीं, रखरखाव को सफलता का मानदंड बनाना होगा। भारत का नेतृत्व शौचालयों की संख्या नहीं, उनकी स्वच्छता, गरिमा और मानवीय संवेदना तय करेगी। स्वच्छ भारत का सबसे गंदा सच बदले, इसकी शुरुआत हर सार्वजनिक शौचालय से हो।

सफेद कोट में बसती है उम्मीद की सबसे बड़ी ताकत

योगेश कुमार गोयल

जब हर उम्मीद टूटने लगती है, तब डॉक्टर ही जीवन की अंतिम आस बनकर सामने खड़े होते हैं। वे केवल रोगों का उपचार नहीं करते बल्कि भय, पीड़ा और निराशा से जूझ रहे परिवारों में विश्वास भी जगाते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें उनके त्याग, सेवा और समर्पण को नमन करने के साथ यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि जीवन बचाने वाले इन देवदूतों को सम्मान, सुरक्षा और संवेदनशील सहयोग देना पूरे समाज का नैतिक दायित्व है।

चिकित्सकों के समाज के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने तथा मेडिकल छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष एक जुलाई को ह्यराष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मुख्रीटे के पीछे: चिकित्सकों का उपचार कौन करता है? विषय के साथ मनाया जा रहा है। यह विषय डॉक्टरों की भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक भलाई को स्वीकार करने और उसका समर्थन करने की आवश्यकता पर बल देता है, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें भी देखभाल और समर्थन की आवश्यकता है जबकि वे अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। वैसे चिकित्सक दिवस मनाने का मूल उद्देश्य चिकित्सकों की बहुमूल्य सेवा, भूमिका और महत्व के संबंध में आमजन को जागरूक करना, चिकित्सकों का सम्मान करना और साथ ही चिकित्सकों को भी उनके पेशे के प्रति जागरूक करना है।

दरअसल कुछ चिकित्सक ऐसे भी देखे जाते हैं, जो अपने इस सम्मानित पेशे के प्रति ईमानदार नहीं होते लेकिन ऐसे चिकित्सकों की भी कमी नहीं, जिनमें अपने पेशे के प्रति समर्पण की कमी नहीं होती। बिना चिकित्सा व्यवस्था के इंसान की जिंदगी कैसी होती, इसकी कल्पना मात्र से ही रोम-रोम सिहर जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चिकित्सकों का महत्व सदा से रहा है और हमेशा रहेगा।

भारतीय समाज में चिकित्सकों को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। हालांकि यह अलग बात है कि निजी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भूमिका पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं लेकिन यह भी सच है कि चिकित्सक लोगों को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से निजात दिलाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। भारत में चिकित्सक दिवस की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और जाने-माने चिकित्सक डा. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में चिकित्सकों की उपलब्धियों तथा चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने वाले डॉक्टरों के सम्मान के लिए इसका आयोजन होता है। वे एक जाने-माने चिकित्सक, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वर्ष 1948 से 1962 में जीवन के अंतिम क्षणों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बिधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी तथा हबरा नामक पांच शहरों की स्थापना की थी। संभवतः इसीलिए उन्हें पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार भी कहा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1911 में एमआरसीपी और एफआरसीएस की डिग्री लंदन से ली। उन्होंने एक साथ फिजिशयन और सर्जन की रॉयल कॉलेज की सदस्यता हासिल कर हर किसी को अपनी प्रतिभा से हतप्रभ कर दिया था। वर्ष 1911 में भारत में ही एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने अपने चिकित्सा कैरियर की शुरूआत की। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए। वर्ष 1922 में वे कलकत्ता मेडिकल जनरल के सम्पादक और बोर्ड के सदस्य बने। 1926 में उन्होंने अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया और 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी चुने गए।

डॉ. बिधान चंद्र रॉय ने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के गठन और भारत की मेडिकल काउंसिल (एमसीआई) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बड़े-बड़े पदों पर रहने के बाद भी वे प्रतिदिन गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना समस्त जीवन चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता की पहुंच के भीतर लाने के लिए वे जीवन पर्यन्त प्रयासरत रहे।4 फरवरी 1961 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ह्यभारत रत्नह्व से सम्मानित किया गया। 1967 में दिल्ली में उनके सम्मान में डा. बी.सी. रॉय स्मारक पुस्तकालय की स्थापना हुई और 1976 में उनकी स्मृति में केन्द्र सरकार द्वारा डा. बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। संयोगवश डा. रॉय का जन्म और मृत्यु एक जुलाई को ही हुई थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हृदयाघात से कोलकाता में हुई थी।

भारत के अलावा दूसरे देशों में भी चिकित्सकों के सम्मान में ऐसे ही दिवस मनाए जाते हैं किन्तु वहां उनका आयोजन अलग-अलग तारीखों में होता है। वैसे चिकित्सक दिवस की शुरूआत सबसे पहले अमेरिका के जॉर्जिया में हुई थी। वहां चिकित्सकों के सम्मान के लिए एक दिन निश्चित करने का सुझाव जॉर्जिया निवासी डा. चार्ल्स बी एलमंड की पत्नी यूडोरा ब्राउन एलमंड ने 30 मार्च 1933 को दिया था।30 मार्च 1958 को यूएस के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने उनके उस सुझाव को स्वीकार करते हुए यह दिवस मनाना शुरू किया। वहां इसके लिए 30 मार्च की तारीख इसलिए रखी गई क्योंकि जॉर्जिया में इसी दिन डा. क्राफोर्ड डब्ल्यू लॉंग ने पहली बार ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का उपयोग किया था। जहां अमेरिका में 30 मार्च को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वहीं वियतनाम में इसकी स्थापना 28 फरवरी 1955 को हुई थी और वहां तभी से 28 फरवरी को या उसके आसपास वाले किसी दिन यह दिवस मनाया जाता है। ब्राजील में महान चिकित्सक रहे कैथोलिक चर्च के सेंट ल्यूक के जन्मदिवस के अवसर पर 18 अक्तूबर को जबकि क्यूबा में पीले बुखार पर शोध करने वाले चिकित्सक कालीस जुआन फिनले के जन्मदिवस 3 दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है। नेपाल में यह दिवस नेपाल मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना के बाद 4 मार्च को तथा ईरान में महान चिकित्सक एविसेना के जन्मदिवस के अवसर पर 23 अगस्त को मनाया जाता है।

बहरहाल, चूंकि चिकित्सकों को पृथ्वी पर भगवान का रूप माना गया है, इसलिए समाज की भी उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वे अपना कर्त्तव्य ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। हालांकि निजी अस्पतालों के कुछ चिकित्सकों पर मरीजों और उनके परिजनों के साथ लापरवाही और लूट के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। दरअसल निजी चिकित्सा तंत्र मुनाफाखोरी के व्यवसाय में परिवर्तित हो चुका है लेकिन फिर भी इस दौगर सच को भी नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना हो या कैंसर, हृदय रोग, एड्स, मधुमेह इत्यादि कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों से चिकित्सक ही करोड़ों लोगों को उबारते हैं। चूंकि चिकित्सक प्रायः मरीज को मौत के मुंह से भी बचाकर ले आते हैं, इसीलिए चिकित्सकों को भगवान का रूप माना जाता रहा है। चिकित्सा केवल पैसा कमाने के लिए एक पेशा मात्र नहीं है बल्कि समाज के कल्याण और उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए चिकित्सक को सदैव सम्मान की नजर से देखने वाले समाज के प्रति उनसे भी समर्पण की उम्मीद की जाती है।

अखिल भारतीय उत्कृष्ट बहुउद्देशीय संस्था का स्थापना दिवस समारोह में नए सदस्य हुए सम्मानित

डॉ मानसी बोलीं : सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण से बहनों को स्वावलंबन की दिशा में सराहनीय काम

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

अखिल भारतीय उत्कृष्ट बहुउद्देशीय संस्था का स्थापना दिवस और सम्मान समारोह रविवार 28 जून 2026 को भिलाई होटल स्थित इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र, बैच और नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. मानसी ने संस्था की कार्यप्रणाली और सदस्यों के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के तहत सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर बहनों को स्वावलंबन की दिशा में संस्था का काम सराहनीय है।

विशिष्ट अतिथि सजीव सर ने कहा कि संस्था सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है। इम्पैक्ट इंडिया में भारत के 100 बेस्ट एनजीओ और

अध्यक्षों का सम्मान इंदौर में किया गया। इससे प्रमाणित होता है कि अ भा उ ब संस्था सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्य वक्ता डी एन शर्मा ने कहा कि गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब उसका इंजन सही हो। उन्होंने संस्था की अध्यक्ष और सभी सदस्यों की प्रशंसा करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। रजनी बघेल ने सभी कर्मठ सदस्यों की सराहना की और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

नए सदस्य और सलाहकार सम्मानित

रजनी बघेल ने नए सदस्यों संगीता आस्थाना, डॉ बीना सजीव, राजेश आस्थाना, भारती बेन, पुष्पा चौहान, तब्बसुम खान और खुशबू सिंग को माला, बैच और सदस्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सलाहकार समिति के सदस्य प्रो डी एन शर्मा, डॉ हंसा शुक्ला और प्रदीप भट्टाचार्य को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के सभी गणमान्य सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र और बैच प्रदान किए गए।

संस्था की अध्यक्ष शानू मोहनन ने साल भर की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने आय व्यय और एक्शन प्लान की जानकारी सदस्यों के सामने रखी। कार्यक्रम में अभिलाषा मिश्रा, शेफाली भट्टाचार्य, शैलजा नायर, राजेंद्रन नायर, संगीता आस्थाना, राजेश आस्थाना, विजय लक्ष्मी, संयोजिका सागरिका पाढी, भारती देवांगन, सुनंदा चंद्राकर, सोनम गुप्ता, खुशबू सिंग, पुष्पा चौहान, तब्बसुम खान, भारती बेन, उमा नायर, क्रिश यादव समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन भारती देवांगन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शानू मोहनन ने दिया। कार्यक्रम का समापन जनगणमन के साथ हुआ।

खास खबर

स्कूलों में मंत्रोच्चार पर हाईकोर्ट की मुहर, याचिका खारिज, शिक्षा मंत्री बोले, मूल्यपरक शिक्षा को मिली कानूनी मजबूती

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ की शासकीय शालाओं में मंत्र और प्रार्थना संबंधी राज्य शासन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी ने दायर की थी। इसमें 12 जून 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्र एवं प्रार्थना संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी।

संविधान उल्लंघन का था दावा : याचिका में कहा गया था कि विद्यालयों में मंत्रोच्चार का आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जाए। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की एकलपीठ में हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर राज्य शासन के आदेश को बरकरार रखा।

'मूल्यपरक शिक्षा को बल मिला' : निर्णय का स्वागत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। सरकार शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, सकारात्मक सोच, राष्ट्रभावना और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति सम्मान विकसित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के साथ मूल्यपरक शिक्षा को भी महत्व दे रही है। विद्यालयों में प्रार्थना और मंत्रोच्चार का उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में एकाग्रता, आत्मविश्वास, अनुशासन और संस्कारों का विकास करना है। मंत्री यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य सरकार की पहल को कानूनी मजबूती मिली है। इससे विद्यालयों में संस्कारयुक्त शिक्षा को बढ़ाने के प्रयासों को नया बल मिलेगा। राज्य सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय

एआई मिशन के जरिए युवाओं को कौशल, रोजगार और नवाचार के मिलेंगे नए अवसर

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास एवं विस्तार, मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेवा सेतु, ई-प्रगति पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एवं एनालिसिस सिस्टम), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स तथा विभिन्न डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने तथा तकनीक आधारित सुशासन को नई गति देने के विभिन्न आयामों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रभावी माध्यम है। एआई के प्रभावी उपयोग से शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं है, बल्कि प्रदेश के लोगों को एआई के लिए तैयार करना, व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाना, नागरिकों की आय में वृद्धि करना तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में एआई के व्यापक उपयोग से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य में मजबूत एआई

इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा तथा सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार एआई के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में प्रस्तुत विजन दस्तावेज में बताया गया कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में एआई सीख सके, सरकार तकनीक आधारित भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करे और उद्योगों तथा व्यवसायों को नई गति मिले। इस मिशन के अंतर्गत पांच प्रमुख स्तंभों – एआई कौशल विकास, नवाचार एवं स्टार्टअप, जागरूकता एवं आउटरीच, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई तथा शासन में एआई के उपयोग – पर कार्य किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों तथा सरकारी कमर्चारियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम, एआई एवं रोबोटिक्स क्लब तथा हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में एआई सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, छात्र परियोजनाओं के लिए अनुदान, आईटीआई में एआई लैब तथा विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। राज्य में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई आधारित स्टार्टअप, डेटा सेट तथा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा, सीड फंडिंग तथा उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अत्याधुनिक एआई आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की भी काययीजना प्रस्तुत की गई।

बैठक में सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई उपयोग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर एआई नीति तैयार की जाएगी, जिसमें डेटा सुरक्षा, नागरिकों की निजता का संरक्षण, नियमित तकनीकी ऑडिट तथा केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। शासन में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न विभागों में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी, प्रत्येक विभाग का अलग रोडमैप तैयार होगा, एआई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी एआई पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सुलभ और समावेशी बन सकें।

राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा

बैठक में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले ढाई वर्षों में डीबीएन वित्तपोषित लगभग एक हजार मोबाइल टॉवर स्थापित कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त 577 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 406 टावरों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 171 प्रकरणों का निराकरण आगामी एक माह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भारतनेट फेज-3 की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आईपी-एमपीएलएस आधारित एकीकृत नेटवर्क विकसित किया जाएगा तथा गांवों तक एफटीटीएच सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो सकें और डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वतर्मान में राज्य के 36 विभागों की 520 सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें 111 होस्टेड तथा 409 रीडायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। प्रदेशभर में संचालित 16 हजार 726 सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक सेवा सेतु के माध्यम से 39.75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37.52 लाख आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण करते हुए 94.3 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेवा सेतु में क्यूआर आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण, डिजिलॉकर एकीकरण, ट्रेजरी एवं ई-चालान प्रणाली तथा डीबीटी आधारित भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे सेवाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बैठक में नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स, सुरक्षा संचालन केंद्र, जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली तथा डिजिटल निगरानी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन पहलों से प्रदेश में आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र को नई गति मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा हजारों युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक , सुशासन तथा अभिसरण विभाग के संयुक्त एवं चिप्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मयंक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से सौजन्य भेंट कर महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

इस दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने हालिया बस्तर संभाग प्रवास की जानकारी साझा करते हुए क्षेत्र में किए गए निरीक्षणों, जनसंवाद कार्यक्रमों तथा जमीनी स्तर पर प्राप्त अनुभवों एवं निष्कर्षों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बस्तर के दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों में संचालित योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों एवं संभावनाओं की भी जानकारी दी। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, दूरस्थ क्षेत्रों में पोषण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण तथा आगामी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी का मार्गदर्शन एवं सुझाव प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी, समावेशी एवं जनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर आक्रामक तरीके से जनता की लड़ाई लड़ना है

शिविर से लौट कर आए भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने प्रशिक्षण को बताया उपयोगी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर से लौट कर आए भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर का कहना है कि उन जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रशिक्षण शिविर काफी मायने रखता है। 10 दिवसीय शिविर में हमने बहुत कुछ सीखा। शिविर के समापन पश्चात निर्णय हुआ कि हमें एकजुट होकर प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर आक्रामक तरीके से जनता की लड़ाई लड़ना है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने हमको संगठन की जो शक्ति दी है, उसका उपयोग करके हमें मोदी सरकार और राज्य सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाते रहना है।

श्री चंद्राकर ने कहा कि शिविर का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाना, कार्यकर्ताओं को जनसरोकारों से जोड़ना तथा कांग्रेस की संगठनात्मक कार्य शैली को और प्रभावी बनाना था। यह शिविर केवल संगठनात्मक प्रशिक्षण नहीं बल्कि जनसेवा, अनुशासन और जनता से सीधे जुड़ने की नई सीख देने वाला रहा। अब कांग्रेस को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाना है। साथ ही जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना है। आने वाले समय में भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी जनहित के मुद्दों पर और

अधिक सक्रियता के साथ कार्य करेगी।

श्री चंद्राकर ने बताया कि शिविर के पहले दिन हमारे नेता राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों से संवाद करते हुए संगठन की मजबूती, वतर्मान राजनीतिक परिस्थितियां, जनता के बीच कांग्रेस की भूमिका तथा आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। राहुल गांधी ने प्रशिक्षण के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया कि कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी जनता की आवाज बने। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करें।

श्री चंद्राकर ने बताया कि शिविर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जिला अध्यक्षों का हौसला बढ़ाया। श्री बघेल ने अपने संबोधन में देश की आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के योगदान, संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच लगातार सक्रिय रहकर उनकी समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना होगा।

श्री चंद्राकर ने बताया कि शिविर के दौरान अभनपुर विधानसभा के ग्राम लखना में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होना एक रोमांच की तरह था। मनरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों के साथ सभी जिला अध्यक्षों ने 2 घंटे तक श्रमदान किया। श्रमदान के दौरान श्रमिकों के श्रम, संघर्ष और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को निकट से देखने और समझने का अवसर मिला। इस तरह के प्रशिक्षण से हम सीधे समाज और श्रमिक वर्ग से जुड़े और जनता की समस्याओं को और बेहतर ढंग से समझ सके। अब इस प्रशिक्षण को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी हम सब पर है।

सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा मंच, वार्षिक आयोजनों के लिए कलाकारों से आवेदन आमंत्रित

15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन, शास्त्रीय संगीत, लोककला, नाट्य और वाद्ययंत्र प्रस्तुतियों के लिए होगा चयन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी।

संस्कृति विभाग प्रतिवर्ष प्रदेशभर में विभिन्न सांस्कृतिक

आयोजनों का आयोजन करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां शामिल रहती हैं। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए पावस प्रसंग (शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य), रंगतरंग वाद्ययंत्र संगम, रंगपरब नाट्य श्रृंखला तथा लोकरंग पर्व के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा।

विशेष रूप से लोकरंग पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककलाओं एवं लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भरथरी, पंडवानी, ढोलामारू, लोरिकचंदा, नाचा, गम्मत, सुआ, करमा, पंथी, बांसगीत, देवारगीत, ददरिया, जसगीत, संस्कार गायन सहित अन्य पारंपरिक लोकविधाओं में दक्ष कलाकार आवेदन कर सकते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की लोक-सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराना है।

आवेदन करने वाले कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों का चिन्हारी पंजीकरण होना आवश्यक है तथा समूह प्रस्तुति के इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, द्वितीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यवसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित ई-मेल के माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

संस्कृति विभाग ने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की है। विभाग ने प्रदेश के पात्र कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की अपील की है।

डायरिया मुक्त जिले के लिए दो माह का विशेष अभियान शुरू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वर्षा ऋतु में बच्चों को डायरिया एवं अन्य जलजनित बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिले में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक श्डायरिया रोको अभियानश संचालित किया जा रहा है। स्वच्छ जल, समुचित उपचार डायरिया से बचें हर बार थीम पर आधारित इस अभियान के माध्यम से पाँच वर्ष तक के बच्चों वाले प्रत्येक परिवार तक स्वास्थ्य सेवाएं एवं जागरूकता संदेश पहुंचाए जाएंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर डायरिया से बचाव एवं उपचार के संबंध में जानकारी देगी। परिवारों को हाथ धोने की सही विधि, ओआरएस घोल बनाने की प्रक्रिया, ओआरएस एवं जिंक के नियमित उपयोग, दस्त होने पर भी बच्चे को स्तनपान जारी रखने तथा शौचालय के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा।

डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के ओपीडी एवं आईपीडी में ओआरएस-जिंक कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। साथ ही जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए पेयजल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करने, संक्रमण रोकने हेतु क्लोरीन टैबलेट वितरित करने तथा आवश्यक दवाओं एवं ओआरएस-जिंक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, स्कूल शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे।

राम कपूर पर बुरी तरह भड़कीं कंगना नेशनल टीवी पर लगा दी क्लास

नेटफ्लिक्स का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'लॉकअप' का सीजन 2 इन दिनों ओटीटी पर धूम मचा रहा है. जेल के अंदर कैदियों के बीच का ड्रामा तो बढ़ ही रहा है. अब तक तो कैदी आपस में भिड़ ही रहे थे, लेकिन अब जेल के अंदर पहले वीकेंड का हिसाब-किताब होने वाला है. मेकर्स ने शो का एक नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. इस वीकेंड शो के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख का साथ देने खुद बॉलीवुड की 'पंगा क्वीन' यानी कंगना रनौत पहुंचने वाली हैं. प्रोमो देखकर साफ है कि कंगना आते ही घरवालों के पहले हफ्ते के खेल की धज्जियां उड़ाने वाली हैं और उनके निशाने पर आने वाले हैं टीवी के बड़े एक्टर राम कपूर.दरअसल, 'लॉकअप 2' के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि कंगना रनौत ने राम कपूर को आड़े हाथों लिया है. कंगना ने बेहद तीखे तेवर दिखाते हुए राम से कहा, राम, गेम को सीरियसली नहीं लेना था, और अगर लगता है कि तुम इस जेल के लिए बहुत बड़े हो, तो यहां आए ही क्यों? अपना ये फुहड़पन दिखाने के लिए?कंगना की बातें सुनने के बाद राम कपूर ने भी अपना बचाव करते हुए जवाब दिया, जब सही वक्त आएगा, तब मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करूंगा और यहां मौजूद किसी भी दूसरे इंसान से बेहतर तरीके से सामने लाऊंगा. लेकिन कंगना कहां रुकने वाली थीं, उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, अगर खुद में सुधार करना चाहते हो, तो अपने बचाव में दलीलें देना बंद करो.राम कपूर के लिए ये हफ्ता वैसे भी विवादों से भरा रहा है. होस्ट फराह खान ने भी उन्हें 'सेफ गेम' खेलने और घर में दुश्मनी मोल न लेने की कोशिश करने के लिए टोका था. इसके अलावा, हाल ही में को-कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला के साथ हुई बहस में राम कपूर ने शादी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या धोखेबाजी का बचाव किया था. राम ने कहा था, 卐अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं, तो कोई भी बात रिश्ता तोड़ने की वजह नहीं बन सकती. शादी एक मुश्किल सफर है, जिस पर रोज काम करना पड़ता है।

जुलाई को आ रही 'ऐल्फा' में आलिया भट्ट लीड रोल में हैं और उनके साथ सपोर्टिंग रोल में शरवरी वाघ दिखने वाली हैं. क्योंकि ये फीमेल स्पाई फिल्म है और लीड एक एक्ट्रेस ही कर रही हैं, तो आलिया भट्ट को ज्यादा फीस मिलना बनता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस इस पिक्चर के लिए 25 करोड़ रुपये तक चार्ज कर रही हैं और शरवरी वाघ के हाथ बस 3 करोड़ रुपये ही आए हैं. अब कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण और कियारा आडवाणी ने इस ह्वत्रह्न स्पाई यूनिवर्स से कितने पैसे वसूले हैं, जान लीजिए.

1. कियारा आडवाणी: 2025 में ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' रिलीज हुई थी, जो पिछले साल की बड़ी फिल्म थी पर फ्लॉप हो गई थी. ऋतिक के सामने फिल्म में जूनियर एनटीआर विलेन बने थे, जिन्होंने काफी फीस वसूली थी. और कियारा आडवाणी ने फिल्म में 'काव्या लूथरा' का किरदार निभाया है, जो रॉ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लूथरा (आशुतोष राणा) की बेटी बनीं. वहीं, विंग कमांडर के रोल के लिए एक्ट्रेस को 15 करोड़ फीस मिली है.

2. दीपिका पादुकोण: अब बारी आती है दीपिका पादुकोण की, जो 'पठान' में शाहरुख खान के अपोजिट दिखी थीं. इस पिक्चर में जॉन अब्राहम विलेन बने थे और फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था. इस फिल्म में बोल्ड लुक के लिए एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. हालांकि, दीपिका पिक्चर में आईएसआई की एक्स एजेंट रुबिना मोहसिन का रोल करती दिखी थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए उन्हें 15 करोड़ ही फीस मिली थी.

3. कटरीना कैफ: टाइगर की जोया इस यूनिवर्स में सबसे पुरानी हैं. वो तब से इस ह्वत्रह्न का हिस्सा हैं, जब मेकर्स ने स्पाई यूनिवर्स यूनिवर्स बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था. वो जोया बनकर तीन फिल्में कर चुकी हैं. 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है' से लेकर 'टाइगर 3' तक, 2012 में पहली फिल्म आई और 2023 में तीसरा इंस्टॉलमेंट लाया गया. बात आज तीसरे पार्ट की करेंगे. टाइगर की पत्नी और एक्स आईएसआई एजेंट बनने के लिए कटरीना को 'टाइगर 3' में 15 से 21 करोड़ तक फीस मिली थी.

4000 करोड़ की रामायण से आगे निकली 500 करोड़ में बनी o iç 6 लाख लोगों पर चला यश का जादू

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश साल 2022 की चत्नस्न 2 के बाद किसी भी पिक्चर में नहीं दिखे हैं. हालांकि, चार सालों के बाद वो गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक' के जरिए कमबैक करने वाले हैं. ये फिल्म इसी साल 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है. पहले मेकर्स ने जनवरी में एक टीजर वीडियो रिलीज करते हुए यश के कैरेक्टर राया को इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद 1 जुलाई को नया टीजर आया, जिसमें इस फिल्म की 5 हीरोइनें की झलक दिखाई गई. इन सबके जरिए मेकर्स ने फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बना दिया है. इस पिक्चर को लेकर इतना ज्यादा बज़ है कि टिकट बुकिंग वेबसाइट बुकमाय शो पर 'टॉक्सिक' रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' से भी आगे निकल गई है.दरअसल, बुकमाय शो पर हर फिल्म के नाम के साथ इंटरेस्ट का एक ऑप्शन होता है, जहां पर क्लिक करके ऑडियंस ये जाहिर करते हैं को वो उस फिल्म को देखने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं. अभी 'टॉक्सिक' को रिलीज होने में लगभग दो महीने का समय है और अब तक इस फिल्म को 6 लाख इंटरेस्ट मिल चुके हैं.यश की 'टॉक्सिक' का बजट लगभग 500 करोड़ रुपये है. वहीं 'रामायण' के दो पार्ट का बजट 4 हजार करोड़ है. बड़े बजट की फिल्म होने के बाद भी 'रामायण' इंटरेस्ट के मामले में 'टॉक्सिक' से बहुत पीछे है. 'रामायण' को अब तक सिर्फ 95 हजार ही इंटरेस्ट मिले हैं. हां, ये जरूर है कि दोनों फिल्मों की रिलीज में लगभग 2.5 महीने का गैप है. लेकिन फिर भी 'रामायण' जैसी बड़े बजट की फिल्म के लिहाज इंटरेस्ट अभी बहुत कम है.'रामायण' का पहला पार्ट इसी साल दिवाली (नवंबर फर्स्ट वीक) के मौके पर रिलीज होने वाला है. वहीं दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली पर आएगा. खास बात ये है कि यश 'टॉक्सिक' में तो हैं ही, साथ ही वो 'रामायण' में भी अहम भूमिका में हैं।

स्मृति मंधाना और शाहरुख खान बने कैंडेरे के ब्रांड एंबेसडर

वैलरी ब्रांड कैंडेरे ने स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। स्मृति मंधाना शाहरुख खान के साथ मिलकर इस ब्रांड का चेहरा बन गई हैं। कल्याण वैलर्स के मशहूर लाइफस्टाइल वैलरी ब्रांड कैंडेरे (ष्ड्डठ्ठस्त्रद्गह्द्ग) ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। अब स्मृति मंधाना, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ मिलकर इस ब्रांड का चेहरा बन गई हैं। कैंडेरे का यह कदम आज के युवाओं और आधुनिक भारतीय ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानें, कौन हैं स्मृति मंधाना? स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक बेहतरीन और स्टार खिलाड़ी हैं। वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और टीम की उप-कप्तान भी हैं। स्मृति ने बहुत ही कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख दिया था और अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में नाम कमाया। उन्हें आईसीसी द्वारा साल की बेस्ट महिला क्रिकेटर का अवॉर्ड भी मिल चुका है। मैदान पर उनके शानदार प्रदर्शन और मैदान के बाहर उनके सादगी भरे स्वभाव के कारण आज वह करोड़ों युवाओं और खासकर लड़कियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं।

कैंडेरे ने स्मृति मंधाना को ऐसे समय में अपने साथ जोड़ा है जब भारत में महिला क्रिकेट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। स्मृति ने अपनी कड़ी मेहनत, लगातार अछे प्रदर्शन और सचे व्यवहार से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। कैंडेरे का मानना है कि स्मृति आज की उस पीढ़ी को दिखाती हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनमें आत्मविश्वास है और जो अपनी शर्तों पर जीती हैं। उनका यही अंदाज ब्रांड की सोच से पूरी तरह मेल खाता है।कैंडेरे का ध्यान उन ग्राहकों पर है जो वैलरी को केवल शादी-ब्याह या बड़े त्योहारों पर पहनने की चीज नहीं मानते, बल्कि उसे अपनी रोज की जिंदगी और फैशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ब्रांड के डायरेक्टर रमेश कल्याणरमन ने कहा कि स्मृति मंधाना का प्रभाव सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है, वह आज के भारत की सोच को दिखाती हैं। शाहरुख खान और स्मृति मंधाना के साथ आने से ब्रांड अब देश के हर तरह के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकेगा और लोगों के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करेगा।इस नए सफर की शुरुआत पर खुशी जताते हुए स्मृति मंधाना ने कहा कि वह कैंडेरे के साथ जुड़कर बहुत एक्साइटेड हैं।

रकुलप्रीत की 9 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म बनी नंबर 1

फ्लॉप तेलुगु फिल्म का हिन्दी वर्जन यूट्यूब पर हुआ सुपरहिट, 100 करोड़ व्यूज के साथ रचा इतिहास

भारतीय सिनेमा में ऐसी कई फिल्में आपको देखने मिल जाएंगी जो भले ही अपने रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह आ गिरीं हों लेकिन समय के साथ उन्हें काफी पसंद किया गया है। इतना ही नहीं कई फिल्में कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शुमार भी हो गई हैं। ऐसे में एक तेलुगु फिल्म, जिसका नाम 'जया जानकी नायका' है, उसने भी एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म एक ही यूट्यूब अपलोड पर 1 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली फीचर फिल्म बन गई है।

निर्देशक बोयापति श्रीनु के निर्देशन में बनी और बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'जया जानकी नायका' करीब 40 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई थी। हालांकि, सिनेमाघरों में यह फिल्म उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई और दुनियाभर में महज लगभग 20 करोड़ रुपये का कारोबार ही कर सकी थी। फिल्म को एक फ्लॉप कैटगरी में शुमार कर दिया गया था।

फिल्म की किस्मत तब बदली, जब 2019 में इसकी रिलीज के करीब दो साल बाद इसे 'खूंखार' नाम से हिंदी में डब करके पेन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। इसके बाद भी ये फिल्म रातों-रात वायरल नहीं हुई, बल्कि पिछले छह सालों में धीरे-धीरे दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाती गई। खासतौर पर उत्तर भारत के दर्शकों ने यूट्यूब के रिकमेंडेशन के जरिए इस फिल्म को ढूंढा और इसके दमदार एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल फैमिली ड्रामा की वजह से इसे बार-बार देखा। इसी लगातार मिलते प्यार ने फिल्म को 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ व्यूज का मुकाम दिला दिया।

इस सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए फिल्म के निर्देशक बोयापति श्रीनु ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 1 बिलियन व्यूज। 1000 मिलियन दिल। 100 करोड़ जज्बात। एक फिल्म। दुनिया की पहली फिल्म, जिसने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। 'जया जानकी नायका (खूंखार)' को हमेशा यादगार बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आप सभी की है। आपके असीम प्यार और लगातार मिले समर्थन के लिए तहेदिल से शुक्रिया।

फिल्म की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल, उनके पति और एक्टर जैकी भगनानी ने इस फिल्म के पोस्टर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए लिखा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है रॉकस्टार। इस स्टोरी को रिपोस्ट करके रकुलप्रीत ने उनका धन्यवाद किया। इसके अलावा एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, कुछ किरदार हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं, और 'जानकी' हमेशा उनमें से एक रहेगी।फिल्म 'जया जानकी नायका' की कहानी बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सिनेमाघरों में यह फिल्म दर्शकों को आकर्षित करने में सफल नहीं रही थी, लेकिन बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। बिना किसी दोबारा थिएटर रिलीज के, फिल्म ने अपनी सबसे बड़ी ऑडियंस सिर्फ यूट्यूब के जरिए बनाई और वहीं से इसे रिकॉर्डतोड़ लोकप्रियता हासिल हुई।

20 साल से सड़क-बिजली का इंतजार, कीचड़ में कैद राहुरपुर-खैरी गांव

बारिश में एंबुलेंस नहीं पहुंचती, चारपाई पर ले जाना पड़ता है मरीज

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले की ग्राम पंचायत राहुरपुर और आश्रित ग्राम खैरी के ग्रामीण पिछले 20 वर्षों से सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। बारिश में गांव की हालत बदतर हो जाती है। कीचड़ से भरी गलियों और बदहाल सड़कों के कारण घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है।

बीमार को चारपाई पर ढोना मजबूरी

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो सबसे बड़ी समस्या उसे अस्पताल पहुंचाने की होती है। कीचड़ के कारण गांव के अंदर तक एंबुलेंस नहीं आ पाती। मरीज को चारपाई या कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। इससे कई बार जान पर बन आती है।

सांप-बिच्छू का खतरा, 2 दिन तक गुल रहती है बिजली

गांव की गलियां कीचड़ और जलभराव से भरी हैं। जगह-जगह पानी जमा होने से सांप, बिच्छू और विषैले जीव-जंतुओं का खतरा बना रहता है। बारिश में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बिजली व्यवस्था भी बदहाल है। कई बार लगातार दो-दो दिन तक आपूर्ति बंद रहती है, जिससे रात अंधेरे में कटती है और बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है।

'चुनाव बाद भूल जाते हैं वादे'

ग्रामीणों का आरोप है कि दो दशकों में कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने मांग रखी गई। आवेदन और शिकायतें भी दीं, लेकिन ठोस पहल नहीं हुई। चुनाव के समय विकास के वादे होते हैं, पर बाद में गांव की समस्याएं भुला दी जाती हैं।

प्रशासन से जल्द निर्माण की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गांव में जल्द पक्की सड़क बनाने, बिजली व्यवस्था सुधारने और मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की है। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर 20 साल से चली आ रही उनकी मांग पर कब गंभीरता दिखाई जाएगी, या उन्हें इसी बदहाल व्यवस्था में जीवन गुजारना पड़ेगा।

खास खबर

चूना पत्थर का अवैध परिवहन करने पर 3 वाहन को किया गया जप्त

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम द्वारा अर्जुनी, रायतापायली, बीजेभांठा, डोंगरगांव, खुज्जी, कुमरदा, लक्ष्मणभरदा, किरगी, सुरगी, सिंघोला, तुमड़ीबोड़, इन्दामारा, सोमनी सहित अन्य क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान चूना पत्थर (गिट्टी) का अवैध परिवहन करने पर 3 वाहनों को जप्त किया गया। इसके तहत ग्राम करेली में कोटगुल महाराष्ट्र निवासी चंदन शेखावत के स्वामित्व के हाईवा एमएच 33 टी 5852 से बिजरावन मध्यप्रदेश निवासी वाहन चालक बहादुर सिंह एवं ग्राम खुर्सीपार में डोंगरगांव निवासी गोविन्द देवांगन के स्वामित्व के माजदा सीजी 08 एएन 8053 से बाजार नवागांव निवासी वाहन चालक उमेश यादव द्वारा चूना पत्थर (गिट्टी) का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए जप्त कर थाना डोंगरगांव को सुपुर्द किया गया। इसी तरह ग्राम फरहद में दुर्ग निवासी अमर इन्क्रा के स्वामित्व के हाईवा सीजी 07 एएक्स 9196 से अज्ञावबाजार निवासी वाहन चालक अभिषेक पाण्डे द्वारा चूना पत्थर (गिट्टी) का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए जप्त कर थाना पुलिस लाईन राजनांदगांव को सुपुर्द किया गया। प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम के लिए लगातार गस्त व निगरानी की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले बनेंगे राह-वीर

मोहला। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने और आमजन को मानवता के इस कार्य के लिए प्रेरित करने हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राह-वीर योजना संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना के बाद शुरुआती एक घंटे यानी गोल्डन ऑवर के भीतर घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके, जिससे उसकी जान बचाई जा सके।

योजना के तहत यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने, एंबुलेंस बुलाने या प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करता है, तो ऐसे व्यक्ति को राह-वीर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने में सहयोग करने वाले व्यक्ति को प्रति घटना 25 हजार रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राह-वीर अवॉर्ड के लिए एक्रॉलेजमेंट फॉर्म संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा दिया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन समिति सिफारिशों पर राह-वीर योजना के लाभार्थी का विवरण एवं अन्य जानकारी ई-डीएआर प्लेटफार्म पर अपलोड करेगे। जिसके पश्चात राज्य सरकार पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पुरस्कार राशि जमा करेंगी। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में अक्सर लोग कानूनी प्रक्रिया या अन्य आशंकाओं के कारण मदद करने से पीछे हट जाते हैं, जबकि गुड समेरिटन संबंधी प्रावधानों के तहत सहायता करने वाले नागरिकों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से संरक्षण दिया गया है। सरकार की यह पहल लोगों में संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों की सहायता के लिए आगे आएं और जरूरतमंदों की जान बचाने में अपनी सहभागिता निभाएं। समय पर की गई छोटी-सी मदद किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। योजना 31 मार्च 2028 तक प्रभावशील रहेगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा के विजन पर अमल : 'मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी' अभियान को मिली रफ्तार

60 ग्राम पंचायतों में चार डिब्बों की व्यवस्था से होगा कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के "स्वच्छ छत्तीसगढ़-समृद्ध छत्तीसगढ़" के विजन को साकार करने की दिशा में कबीरधाम जिले में 'मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी' अभियान को व्यापक रूप से गति दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू के मार्गदर्शन तथा कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलेभर में जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन ही नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाना भी है।

हरा, नीले, लाल और काले डिब्बे से होगा कचरे का सुरक्षित निपटान

पायलट परियोजना के तहत अक्टूबर 2026 तक जिले की 60 ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक घर और सार्वजनिक स्थानों पर चार अलग-अलग रंगों के डिब्बों के माध्यम से कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया जा रहा है। हरे डिब्बे में गीला कचरा, नीले डिब्बे में सूखा कचरा, लाल चिन्हित डिब्बे में सेनेटरी कचरा तथा काले डिब्बे में घरेलू हानिकारक कचरा एकत्र किया जा रहा है। लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि हरा डिब्बा खाद का आधार बनेगा, नीला डिब्बा आय का स्रोत बनेगा, जबकि लाल और काला डिब्बा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए संवेदनशील कचरे के सुरक्षित निपटान का माध्यम हैं।

कचरा अलग करेंगे, बीमारी भगाएंगे- उप मुख्यमंत्री शर्मा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के संदेश "कचरा अलग करेंगे, बीमारी भगाएंगे" को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वच्छता दीदियां और विभागीय अमला लगातार गांवों में सक्रिय है। स्वच्छता दीदियां घर-घर जाकर लोगों को सूखा, गीला, सेनेटरी तथा घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग रखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही ग्रामीणों को कचरा खुले में नहीं फेंकने, नालियों और सड़कों पर कचरा नहीं डालने तथा कचरा नहीं जलाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

स्वच्छता को बनाया जा रहा जनआंदोलन

अभियान के दौरान ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए कपड़े एवं जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए ग्राम सभाएं, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, शपथ कार्यक्रम और जनसंवाद जैसे विविध माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

स्वच्छता को बना रहे एक आदत और सामाजिक जिम्मेदारी

जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम को स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश का आदर्श जिला बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मंशानुरूप इस अभियान का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में "मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी" की भावना विकसित करना है, ताकि स्वच्छता एक आदत और सामाजिक जिम्मेदारी बन सके। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से जिले की सभी ग्राम पंचायतों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संजय सोनी ने बताया कि विभागीय अमला एवं मिशन के कर्मचारी लगातार गांवों का भ्रमण कर लोगों को कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता और जनजागरूकता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ कबीरधाम का सपना साकार होगा।

ग्राम सभाओं और कृषक चौपाल के माध्यम से किसानों को दी जा रही योजनाओं की जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले की ग्राम पंचायतों में किसानों को शासन की कृषि एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम सभा एवं कृषक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने किसानों को शासन की योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए है।

डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम सम्बलपुर में आयोजित ग्राम सभा में फसल परिवर्तन एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में जानकारी दी गई। किसानों को शासन द्वारा धान के स्थान पर दलहन, तिलहन एवं मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर प्रति एकड़ 15 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि, संतुलित उर्वरक उपयोग, बीजीए टांका निर्माण, फसल बीमा योजना तथा अन्य कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत सिवनीकला में आयोजित कृषक चौपाल में फसल विविधीकरण के अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करने पर शासन द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन तथा पीएम-आशा योजना के तहत दलहन एवं तिलहन की खरीदी संबंधी जानकारी किसानों को दी गई। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग एवं उनके लाभों के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत दैहान, कुहीकला, साल्हे एवं रतनभाट में भी कृषक चौपाल आयोजित कर किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा शासकीय प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कृषकों ने भाग लिया। इस अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे।

पार्षद रवि सिन्हा ने बूथों का किया निरीक्षण, बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 39 में पार्षद रवि सिन्हा ने विभिन्न पोलियो बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बच्चों को पोलियो की 'दो बूंद जिंदगी की' पिलाकर अभियान की शुरुआत में सहभागिता निभाई।

निरीक्षण के दौरान पार्षद रवि सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ और मितानिनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी कारणवश कोई बच्चा पहले दिन पोलियो की दवा पीने से वंचित रह गया हो, तो 29 और 30 जून को घर-घर पहुंचने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से न छूटे।

पार्षद ने कहा कि पोलियो उन्मूलन के लिए जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करे। उन्होंने वार्डवासियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, मितानिन, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने और अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने का संकल्प लिया गया।

ढोलढोली रपटे पर बाढ़ में फंसी यात्रियों से भरी मजदा, ग्रामीणों ने बचाई 25 जान

तेज बहाव में बीच धार अटकी गाड़ी, महिलाओं-बच्चों समेत सभी सुरक्षित : हर साल बनता है जानलेवा हालात

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

पंडरिया विकास खंड के वनांचल ढोलढोली रपटे पर गुरुवार शाम बड़ा हादसा टल गया। लगातार बारिश से रपटे पर तेज बहाव के बीच 20 से 25 यात्रियों से भरी एसएमएल माजदा बीच धार में फंस गई। वाहन में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी सवार थे। अचानक गाड़ी रुकते ही चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी फैल गई।

ग्रामीणों ने दिखाई सूझबूझ

घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बिना तेज बहाव में उतरे ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए एक-एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। समय पर मदद न मिलती तो जनहानि हो सकती थी।

दर्जनों गांवों को जोड़ता है रपटा

ढोलढोली रपटा छिंदीडीह, सारपानी, भाकुर, पीपरटोला, सेंदुरखार, देवान पटपर समेत दर्जनों गांवों का प्रमुख मार्ग है। रोज हजारों ग्रामीण इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। हर मानसून में रपटे पर तेज बहाव से आवागमन ठप हो जाता है और लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है।

ऊंचे पुल की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, फिर भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। लंबे समय से यहां ऊंचे पुल के निर्माण की मांग की जा रही है ताकि बरसात में जान जोखिम में डालकर सफर न करना पड़े। घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से बरसात में संवेदनशील रपटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और पुल निर्माण की दिशा में जल्द कार्रवाई की मांग की है।

झटका तार बना मौत का जाल : बेटे को बचाने दौड़े पिता, करंट से दोनों की मौत

सहसपुर लोहारा, कबीरधाम। जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों में लगाए जा रहे अवैध विद्युत झटका तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुए। ग्राम बीरनपुर कला में गुरुवार सुबह करंट की चपेट में आने से किसान गोकरण पटेल (55) और उनके पुत्र परमेश पटेल (22) की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार दोनों सुबह धान की बुआई के लिए खेत पहुंचे थे। खेत की मेड़ पर जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए विद्युत फेंसिंग लगाई गई थी। लगातार बारिश से खेत में पानी भरा था, जिससे करंट का खतरा बढ़ गया। काम के दौरान परमेश अचानक करंट की चपेट में आ गया। बेटे को तड़पता देख गोकरण उसे बचाने दौड़े, लेकिन वे भी करंट से चिपक गए। आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले दोनों की मौत हो चुकी थी।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय-सीमा का रखें विशेष ध्यान-कलेक्टर तुलिका प्रजापति

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सेतु विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सभी स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए औंधी, मोहला एवं चिल्हाटी में निर्माणाधीन महाविद्यालय भवन, मोहला सर्किट हाउस सहित अन्य भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सेतु विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में निर्माणाधीन पुल-पुलियों एवं अन्य सेतु परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराने तथा कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी सड़क निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने, कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की समीक्षा करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, समय-समय पर सत्यापन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने तथा सभी विकास कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने निर्माणाधीन नहरों, जलाशयों तथा सीसी लाइनिंग सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गति लाने, गुणवत्ता बनाए रखने तथा किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बीएसपी की यूनिवर्सल रेल मिल ने रचा इतिहास : जून में 92,073 टन रेल उत्पादन और 89,059 टन प्रेषण का रिकॉर्ड

प्रथम तिमाही में 2,44,028 टन उत्पादन के साथ तकनीकी उत्कृष्टता में भी अव्वल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की यूनिवर्सल रेल मिल ने जून-2026 में उत्पादन और प्रेषण के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूआरएम ने जून में 92,073 टन रेल प्राइम प्रोडक्शन कर विभाग के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन दर्ज किया। इससे पहले मई-2026 में भी मिल ने मासिक उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया था।

सर्वाधिक रेल प्रेषण का कीर्तिमान

जून-2026 में यूआरएम ने 260 मीटर रेल के 94 रेकों के माध्यम से कुल 89,059 टन रेल का सफल प्रेषण किया। यह विभाग के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मासिक रेल प्रेषण है।

तिमाही में भी नया रिकॉर्ड

वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में विभाग ने 2,44,028 टन रेल प्राइम प्रोडक्शन दर्ज कर सर्वश्रेष्ठ तिमाही उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया। तकनीकी उत्कृष्टता में भी मिल ने जून में 97.1 प्रतिशत प्राइम एक्सेप्टेंस यील्ड प्राप्त कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

प्रबंधन ने दी बधाई

इस उपलब्धि पर निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र, कार्यपालक निदेशक ए. के. चक्रवर्ती, पी. के. सरकार, प्रवीण निगम, पवन कुमार, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक तुषार कांत, मुख्य महाप्रबंधक टी. के. कृष्ण कुमार, एच. के. सचदेव, मूर्ति, त्रिभुवन बैठा और उप महाप्रबंधक कामराज ने शॉप फ्लोर पहुंचकर अधिकारियों व कमचारियों को बधाई दी।

निदेशक प्रभारी महापात्र ने कहा कि यह सफलता उत्कृष्ट टीमवर्क, तकनीकी दक्षता और निरंतर बेहतर प्रदर्शन की प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। उन्होंने आगामी लक्ष्यों के लिए इसी समर्पण से काम करने का आह्वान किया।

'सुरक्षा प्रथम' से मिली सफलता

मुख्य महाप्रबंधक योगेश शास्त्री ने इस उपलब्धि को विभाग की सुरक्षा प्रथम कार्य-संस्कृति, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, नवाचार और सहयोगी विभागों के समन्वय का परिणाम बताया। कार्यकारी मुख्य महाप्रबंधक शिशिर शुक्ला ने इसका श्रेय पूरी यूआरएम टीम के सामूहिक प्रयास को दिया। इस मौके पर सी एंड आईटी, आरसीएल, टी एंड डी सहित सहयोगी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया।

बीएसपी प्रवर्तन विभाग का जून में विशेष अभियान 34 आवास व 8 भूखंड कराए गए अतिक्रमण मुक्त

7000 वर्गफीट जमीन कब्जे से मुक्त, 400 से अधिक बैनर-पोस्टर हटाए

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के प्रवर्तन अनुभाग ने जून-2026 में अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान कुल 34 आवास रिक्त कराए गए। इनमें से 8 आवासों के संबंध में संपदा न्यायालय से डिक्री पारित हो चुकी थी।

8 भूखंड और एक दुकान भी मुक्त प्रवर्तन विभाग ने 8 भूखंडों को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 7000 वर्गफीट है। अधिकांश भूखंड व्यवसायिक क्षेत्रों में थे। इसके अलावा एक दुकान को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान 10 दुकानों, आवासों और अन्य भवनों की विद्युत आपूर्ति भी विच्छेदित कराई गई। 80 आवासों की रिक्तीकरण प्रक्रिया में सिविल अभियांत्रिकी विभाग को सहयोग दिया गया।

सड़क सुरक्षा के लिए विशेष अभियान जून में सड़क और यातायात सुरक्षा के लिए दो विशेष अभियान चलाए गए। पहले अभियान में प्रमुख मार्गों से 400 से अधिक अनधिकृत बैनर-पोस्टर हटाए गए और 5 होर्डिंग संरचनाओं को हटाया गया। दूसरे अभियान में एक मार्केट के चौक और मुख्य मार्ग से अनधिकृत सामग्री और शेड के अवैध विस्तार को हटाकर यातायात सुचारु किया गया।

समझाइश से रिक्त हुए 21 रिटेंशन आवास प्रवर्तन विभाग ने कानूनी कारवाई के साथ प्रभावी संवाद और काउंसिलिंग को भी प्राथमिकता दी। इसी पहल से अप्रैल से जून-2026 के दौरान 21 बीएसपी अधिकारियों के रिटेंशन आवास स्वैच्छिक रूप से रिक्त कराए गए।

यह अभियान महाप्रबंधक प्रभारी ए. बी. श्रीनिवास के मार्गदर्शन और सहायक महाप्रबंधक रेमी थॉमस के नेतृत्व में चला। उप प्रबंधक मुकुन्द दास मानिकपुरी, सहायक प्रबंधक देवानंद चौहान, संपदा निरीक्षक भगवान, रमाकांत यादव, राममूर्ति, लक्ष्मन सिंह, बलराम शुक्ला, अजय मिश्रा, कुद्दुद्दीन कुरैशी, ज्ञानचंद जैन, नीरज बाली, राम सहित सुरक्षा कर्मियों की टीम का योगदान रहा।

राजनांदगांव में चाकू के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

राजनांदगांव। सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे एक युवक को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर चाकूबाजी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 2 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि ममता नगर स्थित राजस्थानी होटल के सामने एक व्यक्ति चाकू लेकर किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से खड़ा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रेमन वर्मा, पिता धनसाय वर्मा, उम्र 19 साल, निवासी ग्राम बिजनापुर, ओपी मोहारा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव बताया। तलाशी में उसके पास से एक काले रंग का लोहे का धारदार चाकू बरामद हुआ। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एमएच 40 सीपी 4390, कीमत 18,000 रुपये भी जब्त की गई।

GOSWWAMI
FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
Hoardings • Flex Banner • Vinyl Printing
One Way Vision • Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address - 3rd Floor Shop No-1, Arora Tower, M.G. Market

अर्चना
फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निर्माता एवं विक्रेता
हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई
8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।
संपर्क करें
9329960605, 9827160605, 9098639991

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhilai & Durg
baked.by.suhani
Suhani Singh
Premium Homemade Cakes & Desserts
Serving Bhilai & Durg
DM for Order
Followed by _s_andeep
Follow
Message
Order Now:
@baked.by.suhani
M0.6263734520

10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण
नौकरी में सहायक
प्रवेश प्रारंभ सत्र 2026-2027
निजी कंपनियां जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नौकरियाँ मिलती है।
प्रशिक्षण शुल्क में विशेष छूट
सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)
फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)
कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
ADMISSION HELPLINE: 7697212782

BA
BCA
BCom
BBA
BSc
PGDCA
MSc CHEMISTRY
MSc BIOTECHNOLOGY
MSc BOTANY
MSc ZOOLOGY
MSc COMPUTER Sc
MSc MATHS
MA ENGLISH
MCom
BLib
MLib
DCA
MA CHHATTISGARHI
Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg
SAI COLLEGE
Street-69, Sector-6, Bhilai
70248 86996
99770 01027
Deepak Advertisers

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100